

विमुद्रीकरण : स्तुति करें या भर्त्सना?

“टका माटी, माटी टका”

-रामकृष्ण परमहंस

“सभी भ्रान्तियों में सबसे अधिक अधिकार शून्य तो भविष्यवाणी ही होती है।”

-जार्ज इलियट, मिडलमार्च

विमुद्रीकरण एक क्रांतिकारी एवं अप्रत्याशित कदम है, इसकी अल्पकालिक लागतें हैं, किन्तु दीर्घकालिक लाभ भी हैं। समाचार पत्रों के शीर्ष लेखों में किए गए आग्रह की तुलना में समाज में तरलता की हानि बहुत कम रही और दिसंबर 2016 के अंत से तरलता की स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है। आगे उठाए जा सकने वाले अनेक ऐसे कदम हैं, जिनसे लागतें न्यूनतम हो जाएंगी और विमुद्रीकरण के लाभ अधिकतम स्तर पर पहुँच पाएंगे। इनमें सम्मिलित हैं : तीव्र, मांग के अनुसार, पुनः मुद्रीकरण; और कर सुधार, अर्थात् भूमि एवं भवन संपदा के लेनदेन को जीएसटी के अंतर्गत लाना, करों की दरों और स्टैंप शुल्क को घटाना; और अतिउग्र कर प्रशासकों के उत्साह पर अंकुश लगाते हुए समाज को आश्वस्त करना। इन प्रयासों से संवृद्धि; 2017-18 में अपने सामान्य उन्नयन पथ पर लौट आएंगी, भले ही 2016-17 में इसमें कुछ गिरावट ही दिखाई दे।

I. विषय प्रवेश

3.1 सरकार ने नवंबर 8, 2016 की शाम अर्थव्यवस्था के लिए गंभीर निहितार्थों से भरी एक ऐतिहासिक घोषणा की। तुरन्त प्रभाव से, कुछ एक कार्यों को छोड़कर, दो उच्चतम मूल्य के रू. 500/ और रू. 1000 नोटों का विमुद्रीकरण कर दिया गया।¹ ये नोट अब विधिमान्य करेंसी नहीं रहे। एक झटके में अर्थव्यवस्था के परिचलन की 86 प्रतिशत मुद्रा अवैध घोषित हो गई।² ये नोट दिसंबर 30, 2016 तक बैंकों में जमा कराए जाने थे। दूसरे शब्दों में, आन्तरिक मुद्रा और बैंक जमाओं की परिवर्तनशीलता पर रूकावटें लागू कर दी गई।³

3.2 इस कदम के चार उद्देश्य थे : भ्रष्टाचार पर अंकुश, नकली नोटों की छपाई पर लगाम, आतंकवादियों द्वारा इन उच्च मूल्य नोटों का प्रयोग, और विशेष कर कालाधन संचित करने पर रोक (यह कालाधन कर अधिकारियों के समक्ष घोषित नहीं की गई आय होता है)।

3.3 यह कदम उक्त गैरकानूनी कामों को रोकने के लिए उठाए गए अनेक कदमों के बाद उठाया गया था। ये कदम थे बजट 2014 द्वारा विशेष अन्वेषण दल का गठन; कालाधन और (उस पर) कर अधिनियम, 2015; बेनामी लेनदेन अधिनियम, 2016; स्विट्जरलैंड से जानकारी सांझा करने का समझौता, मॉरीशस, साइप्रस

¹ स्पष्ट रूप से कहें तो कुछ कार्यों को छोड़ शेष सभी के लिए ये नोट विधि मान्य करेंसी नहीं रहे थे। ये कुछ कार्य थे सार्वजनिक सेवाओं के बिलों के भुगतान आदि। किन्तु जन सामान्य के विमर्श में इसे विमुद्रीकरण का नाम मिल गया है। हम भी इसी रूप से इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं।

² इस सारे अध्याय में नकदी, करेंसी, करेंसी/जनता के पास नकदी का पर्यायवाची रूप में प्रयोग होगा।

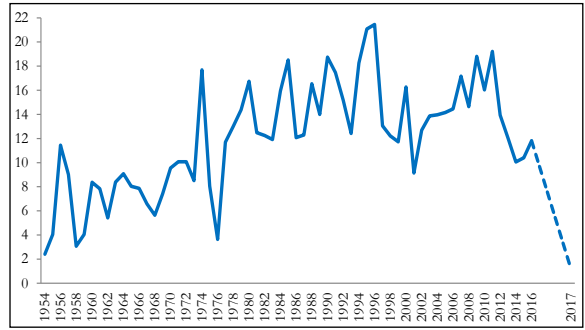
³ नकद को बैंक जमा में बदलना कठिन हो गया था, किन्तु इसे वैधानिक रूप दिसंबर 30, 2016 से निर्दिष्ट बैंक नोट (दायित्व समापन) अध्यादेश द्वारा ही प्रतिबंधित किया गया था।

और सिंगापुर के साथ कर संधियों में परिवर्तन; तथा अघोषित आय की घोषणा योजना। विमुद्रीकरण एक व्यवस्था परिवर्तन का संकेत देने वाला कदम है। यह गैरकानूनी कार्यों तथा उनसे संबंधित धन अर्जन को दंडित करने की सरकार की प्रतिबद्धता की घोषणा थी। साथ ही जिन विधि संगत कार्यों को अभी तक सरकार से छिपाया जा रहा था, उन्हें भी स्थायी रूप से और दंड भरने के साथ घोषित करने का आह्वान था।

3.4 विश्व के आर्थिक इतिहास में भारत की विमुद्रीकरण की घोषणा अप्रत्याशित रही, इसमें सामान्यप्रायः राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद गोपनीयता और आक्समिकता का समावेश रहा। अभी तक सभी विमुद्रीकरण अचानक, किन्तु अतिशय स्फीति, युद्ध, राजनीतिक संकट या अन्य इसी प्रकार की अति पराकाष्ठापूर्ण परिस्थितियों में हुए हैं। किन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था तो स्थिरतापूर्ण समष्टि स्तरीय अर्थ और प्रभावी प्रभावशाली सुधार कार्यों के लागू किए जाने के आधार पर विश्व की तीव्रतम दर पर संवृद्धि कर रही थी (अध्याय-1)। ऐसी सामान्य परिस्थितियों में यदि विमुद्रीकरण करते भी हैं तो वह यूरोप की भांति धीमे-धीमे कदमों में किया जाता है (देखें परिशिष्ट-1, इसमें धीमे-धीमे एवं अचानक किए गए विमुद्रीकरणों की देशानुसार सूची दी गई है)।

3.5 भारत का यह कदम इसके अपने इतिहास की दृष्टि से अभूतपूर्व नहीं है : पहले भी दो बार, 1946 और 1970 में विमुद्रीकरण किए गए हैं, किन्तु 1970 के कदम का नकदी की सफलभता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, जैसा रेखाचित्र-1 में दिखाया गया है⁴ किन्तु अभी उठाए गए कदम बहुत बड़े, किन्तु अस्थायी करेंसी प्रभाव रहे हैं। रेखाचित्र-1 में 1953 से वार्षिक करेंसी प्रतिशत परिवर्तन दिखाए गए हैं। वर्ष 2016-17 के लिए यह परिवर्तन पिछले वर्ष की तुलना में मात्रा 1.2 प्रतिशत (ऋणात्मक) रहेगा। यह पिछली चार मुद्रा की कटौती की घटनाओं से 2 प्रतिशत अंकों से अधिक कम है। उन घटनाओं की औसत करेंसी कटौती लगभग 3.3 प्रतिशत थी।⁵

रेखाचित्र 1 : जनता के पास करेंसी की औसत में वृद्धि (प्रतिशत वर्षानुसार)



स्रोत : समीक्षा की गणनाएं

नोट : यहां वित्तीय वर्ष दिखाए गए हैं, वह भी केवल सम वर्ष।

3.6 वैश्विक वित्तीय संकट के बाद से अनेक विकसित देशों ने मौद्रिक नीति का प्रयोग संवृद्धि प्रोत्साहन के लिए किया है, यह क्रम ऋणात्मक ब्याज की दरों तथा “हैलीकॉप्टर द्वारा नोटों की वर्षा” जैसी अचिन्त्य नीतियों तक चला गया है। भारत के कदम ने तो गैर परंपरागत मौद्रिक नीति को एक नया ही स्वरूप प्रदान कर दिया है। विकसित देश तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि करने में जुटे थे, किन्तु भारत ने तो उसे घटा दिया है। इस नीति को एक “विपरीत हैलीकॉप्टर करेंसी वर्षा” का नाम दिया जा सकता है। संभवतः “हैलीकॉप्टर द्वारा अवशोषण” अधिक उपयुक्त शब्द होगा।

3.7 विमुद्रीकरण पर लोक विमर्श में तीन प्रकार के प्रश्न समूह उठाए गए हैं। पहले समूह में इस कदम को लागू करने में निहित रचना एवं कार्यविधि से जुड़े प्रबंधन विषयक प्रश्न हैं। दूसरे प्रश्न अल्प एवं मध्यकालिक आर्थिक प्रभावों से संबंधित हैं, और तीसरे प्रश्न भविष्य में आर्थिक नीतियों के संचालन के आधारिक बृहतर जीवन दर्शन के प्रति निहितार्थों से जुड़े हैं। यह समीक्षा पहले समूह के प्रश्नों के लिए एक उचित मंच नहीं है तथा तीसरे समूह पर हम अध्याय-1 में चर्चा कर चुके हैं। वर्तमान अध्याय में हमारा ध्यान केवल दूसरे समूह के प्रश्नों पर केंद्रित रहेगा।

3.8 पृष्ठभूमि के तथ्य क्या हैं? विश्लेषण कैसे किया जाए? दीर्घकालिक हितलाभ क्या होंगे तथा अल्पकालिक लगातार क्या हैं? साथ ही, किस प्रकार की नीति प्रतिक्रियाएं

⁴ वर्ष 1970 में सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश के.एन बान्चू की अध्यक्षता वाली कालेधन को कोट से विमुक्ति पर समिति ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में 10 और 100 के नोट बंद करने की सिफारिश की थी। उस समय इन्हीं नोटों का मान 86.65 प्रतिशत मुद्रा के समान था।

⁵ उन चार घटनाओं के समय औसत मौद्रिक जीडीपी संवृद्धि दर 3.5 प्रतिशत थी।

आगे की ओर बढ़ते हुए हितलाभों को अधिकतम एवं लागतों को न्यूनतम बना पाएंगी? यह अनुच्छेद इन्हीं प्रश्नों के उत्तर तलाश करने का प्रयास कर रहा है। समीक्षा में बृहतर क्षेमशास्त्रीय और अन्य गैर आर्थिक आयामों पर चिंतन नहीं किया जाता (राय, 2016)। रोजगार में कमी, कृषि आय में हानि, और अर्थव्यवस्था के नकद सघन अनौपचारिक क्षेत्रकों में सामाजिक असंतोष की सूचनाएं आई हैं। किन्तु समष्टि आर्थिक जानकारी के अभाव में इन सब का व्यवस्थित रूप से विश्लेषण नहीं हो पाएगा।

3.9 एक चेतावनी देना भी उपयुक्त रहेगा। विमुद्रीकरण एक अनुठा कदम है, यह पिछली व्यवस्था से एक संरचनात्मक विलगाव का प्रतिनिधित्व कर रहा है। इसका अर्थ है कि इसके प्रभावों का (पुराने चिन्तन के आधार पर) पूर्वाकलन कर पाना एक जोखिम भरा काम होगा। अतः आगामी चर्चा, विशेषकर परिमाण निर्धारण के प्रयासों को निश्चयत्मक नहीं, किंचित अनुमानात्मक ही मानना चाहिए। इतिहास के फैसला, जब भी वह समय के धुंधलके, को चीरता हुआ आएगा, आज के निष्कर्ष निदानवादों को अर्चभित कर सकता है।

II. पृष्ठभूमि के तथ्य

3.10 भ्रम का निवारण करते हुए मुद्दों की सटीक समझ पाने के लिए शुरू में ही कुछ भेद स्पष्ट कर देने चाहिए। 'नकद' को दो आयामों/स्वरूपों में जाना जा सकता है : इसके कार्यों तथा इसके स्वरूप/स्रोतों के रूप में कार्य-स्वरूप में नकद विनिमय का माध्यम तथा धन के अन्य स्वरूपों, स्वर्ण या फिर भू-भवन संपदा, की भांति मूल्य का भंडार हो सकता है। स्वरूप की दृष्टि से नकदी विधिग्राह्य मुद्रा हो सकती है या फिर गैरकानूनी भी।

3.11 कार्य और स्वरूप बहुत ही पृथक-पृथक होते

हैं। उदहारकण के लिए मूल्य के भंडार के रूप में रखी गई नकदी श्वेत (परिवार द्वारा आक्समिकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से नकद रूप में रखी गई बचत) हो सकती है। दूसरी ओर लेनदेन के लिए प्रयुक्त नकदी का स्रोत, यदि कर वचना या भ्रष्टाचार हो, तो यह कालाधन हो सकता है। ये वर्ग निरूपण कदाचित अस्थिर ही होता है, कई प्रकार की गतिविधियों और कराधिकारियों के समक्ष घोषणा करते हुए जुर्माना चुका कर कालेधन को श्वेत बनाना भी संभव होता है।

3.12 कुछ एक तत्व सार्थक हैं और उन्हीं ने विमुद्रीकरण की प्रेरणा भी दी है।

3.13 सबसे पहले तो भारत में नकद जीडीपी अनुपात का विकास क्रम दो सोपानों में हुआ है। पहले डेढ़ दशकों में (1952-53 से 1967-68 तक) यह लगभग 12 प्रतिशत से घटकर 9 प्रतिशत के आसपास रह गया था। उसके बाद से यह अनुपात अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर के साथ-साथ बदलता रहा है। जब 1970 के दशक के अंत में संवृद्धि दर में सुधार होने लगा तो यह नकद जीडीपी अनुपात भी ऊपर की ओर उठने लगा। वर्ष 2000-2010 में जब संवृद्धि में उफान आया तो इस अनुपात की वृद्धि भी त्वरित दर से होती दिखी। वर्ष 2010 के आसपास स्फीति की दर उच्च रही और उस समय यह अनुपात कुछ कम हो गया था, किन्तु 2014-15 के बाद स्फीति दर में गिरावट के बाद यह अनुपात पुनः 12 प्रतिशत पर पहुँच गया। उच्चमान के करेसी नोटों (रु. 500 तथा रु. 1000) के मूल्य और जीडीपी का अनुपात भी जीवन स्तर के उन्नयन के साथ-साथ ऊपर उठता रहा है (देखें रेखाचित्र-2 के दूसरे भाग में हरित रेखा)।

3.14 दूसरे, भारत की अर्थव्यवस्था, भले ही यह एक अपेक्षाकृत गरीब देश माना जाता हो, किसी सीमा तक अधिक नकदी पर निर्भर रहती है। रेखाचित्र-3 में नकद

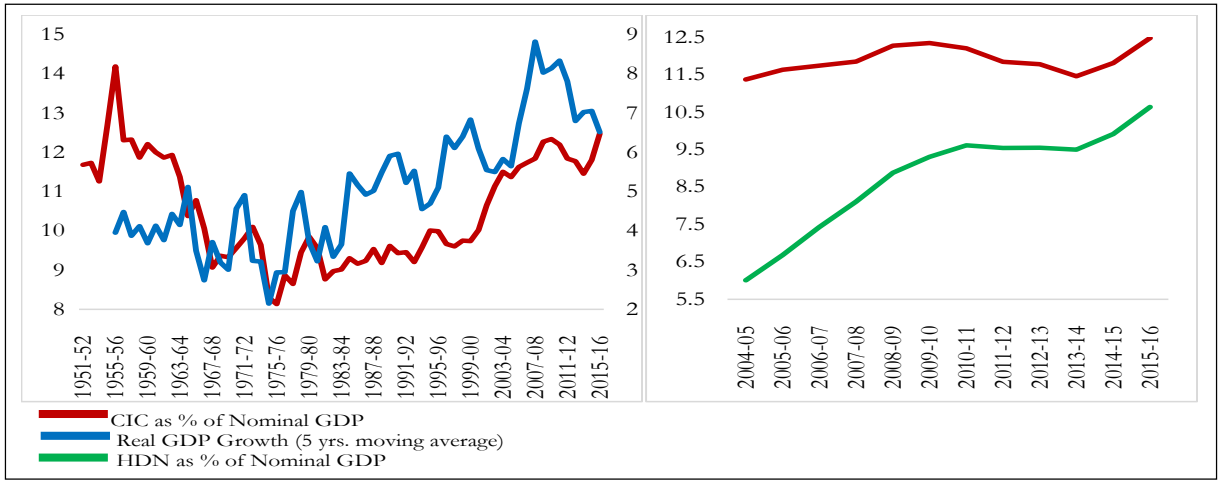
तालिका 1 : नकदी के दो आयाम

श्वेत धन	काला धन
विनिमय	छोटे उद्यम आदानों की नकद खरीद करते हैं, वे स्वयं और उन्हें वह आदान बेचने वाले, दोनों ही इस लेनदेन की कर अधिकारियों के समक्ष घोषणा नहीं करते।
मूल्य का भंडार	परिवार आक्समिकताओं हेतु बचत का कुछ अंश व्यापारी अघोषित धन जमा रखते हैं ताकि चुनाव के समय अपने चहेते उम्मीदवारों को बांट सकें।

जीडीपी अनुपात को प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय (GNI) के अनुसार अंकित किया गया है। यह कथई रंग की रेखा दिखा रही है कि विकास के स्तर में सुधार के साथ-साथ नकद जीडीपी अनुपात में कमी आती है। भारत में यह अनुपात अपने समवर्ती आय समूह (बीच वाले चित्र खंड में दर्शित) में भी अपेक्षाकृत उच्चतर ही है।

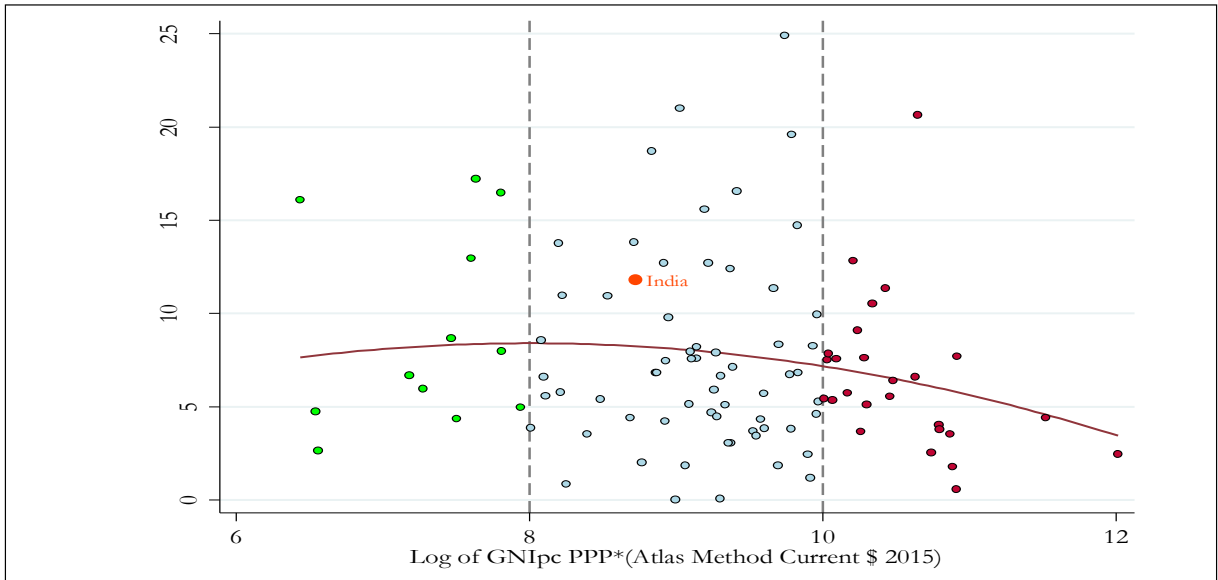
3.15 इससे संकेत मिलता है कि संभवतः नकदी के कुछ भंडार विधिसंगत लेनदेन के लिए नहीं बल्कि भ्रष्टाचार जैसी अन्य गतिविधियों के लिए जमा किए जा रहे थे⁶ यह पूर्वधारणा बहुत प्रबल है, विश्वभर में गलत कार्यों और नकद के बीच गहरा रिश्ता पाया जाता है : जितना अधिक नकदी का परिचलन होता है, देश में (ट्रान्स्पैरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा मापित) भ्रष्टाचार भी उतना ही अधिक होता है (रेखाचित्र-4)।

रेखाचित्र 2 : परिचलन में करेंसी, उच्चमान नोट और वास्तविक जीडीपी संवृद्धि



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

रेखाचित्र 3 : नकद जीडीपी अनुपात बनाम प्रतिव्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय, क्रय शक्ति तुल्य इकाइयों में



स्रोत : विश्व विकास सूचक; अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय आंकड़े

⁶ यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि भ्रष्टाचार से कमाई गई आय काली कमाई ही होती है, किन्तु अधिकांश काली कमाई का माध्यम पूर्णतः विधि संगत होता है। अधिकतर मामलों में वह कमाई इसलिए कालाधन बन जाती है कि कर अधिकारियों के समक्ष उसकी घोषणा नहीं होती। शंकर आचार्य और सहयोगी द्वारा NIPFP के लिए तैयार एक रिपोर्ट 1985 में इन प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा हुई है।

3.16 इस रूप में अर्थव्यवस्था में नकद के चलन को कम करने के प्रयासों से भ्रष्टाचार निवारण रूपी दीर्घकालिक हितलाभ संभव है। किन्तु भारत की स्थिति सामान्य समाश्रयण (प्रतीपगमन) वक्र से उच्चतर है, अर्थात् यहां भ्रष्टाचार के स्तर की तुलना में नकद का व्यवहार अधिक होता है। इसके दो संभावित कारण स्रोत हो सकते हैं। संभवतः भारत में भ्रष्टाचार तथा इसी प्रकार की व्याधियां अनुमानों से कहीं अधिक गहरे पैठी हुई हैं, अर्थात् नारंगी बिन्दु वर्तमान से कहीं दाहिनि ओर होना चाहिए। या फिर संभव है कि अनेक विधिसंगत कार्यों के लिए भी नकदी का ही प्रयोग होता है।

3.17 किन्तु यदि नकदी की जरूरत अधिक है तो इसका अर्थ यह नहीं होगा कि बड़े नोट ही जरूरी है। सामान्यतः बड़े नोट इस कारण भ्रष्टाचार से जुड़े हुए पाए जाते हैं कि उन्हें रखना तथा लाना-लेजाना छोटे नोटों तथा स्वर्ण जैसे अन्य मूल्यवान पदार्थों की अपेक्षा अधिक आसान रहता है। (सैन्ड्स, 2016; हेनरी, 1980; सम्मर्स, 2016; रोगोफ, 2016)।

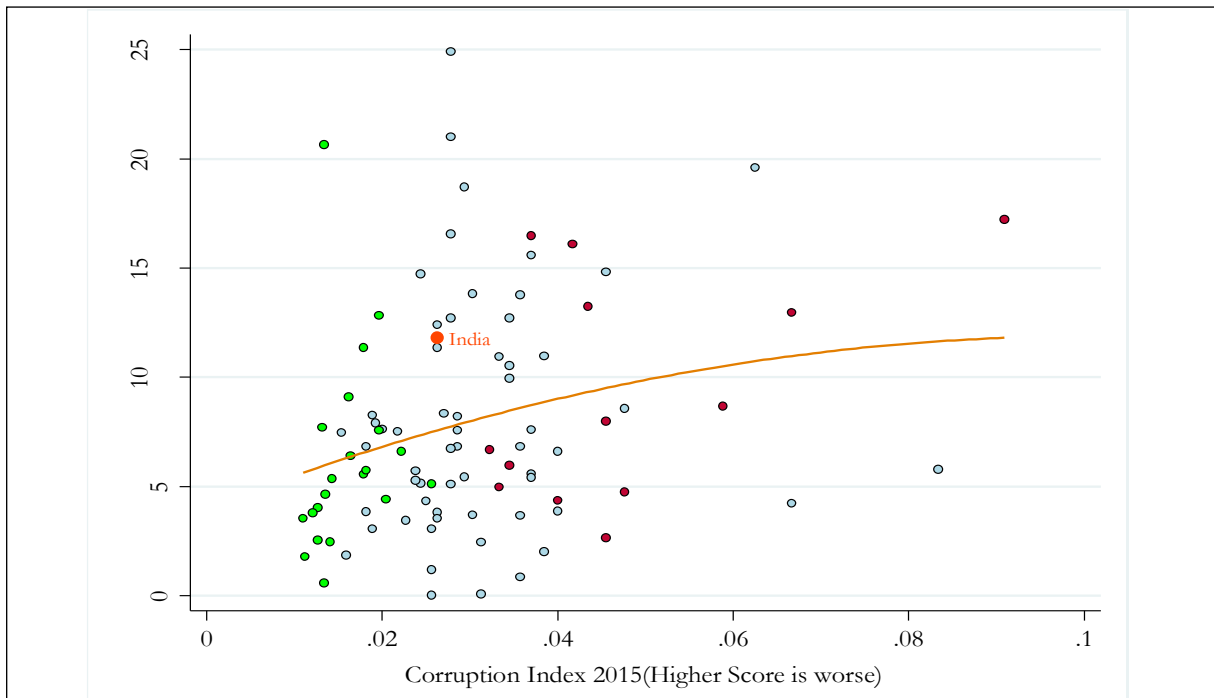
3.18 भारत में उच्चमान नोटों का लेनदेन उनके

मूल्य भंडार स्वरूप से कितना अधिक (उच्च) था? रेखाचित्र-5, 6 इस बात पर कुछ प्रकाश डाल रहे हैं। मौद्रिक प्रतिव्यक्ति आय के सापेक्ष नोटों के मूल्य पर ध्यान देना तो विशेष उपयोगी रहेगा। नोट का आकार आय से जितना अधिक होगा उसकी किसी सामान्य लेनदेन में प्रयोग की संभावना उतनी ही कम होगी? भारत में पिछली एक चौथाई सदी में यह नोट मान आय अनुपात बड़ी तेजी से कम हुआ है, कारण यही रहा है कि आय में वर्तमान उच्चतम नोट मान की अपेक्षा तेजी से वृद्धि हुई है (रेखाचित्र-5)। इससे यही संकेत मिलता है कि बड़े नोट सामान्य लेनदेन में अधिकाधिक प्रयोग हो रहे हैं।

3.19 विभिन्न देशों के आंकड़ों की तुलना इसी धारणा की पुष्टि करती है। यहां स्पष्ट हो रहा है कि अन्य करेसियों के समूह में हमारा रू. 1000 का नोट तो निम्न मध्यम आय वर्ग की अर्थव्यवस्था के समूह में लगभग बीच में ही था (रेखाचित्र-6)।

3.20 संभवतः रू. 500 और रू. 1000 के नोटों के प्रयोग के स्तर को लेकर सबसे सशक्त साक्ष्य तो नोटों

रेखाचित्र 4 : नकद जीडीपी अनुपात और भ्रष्टाचार



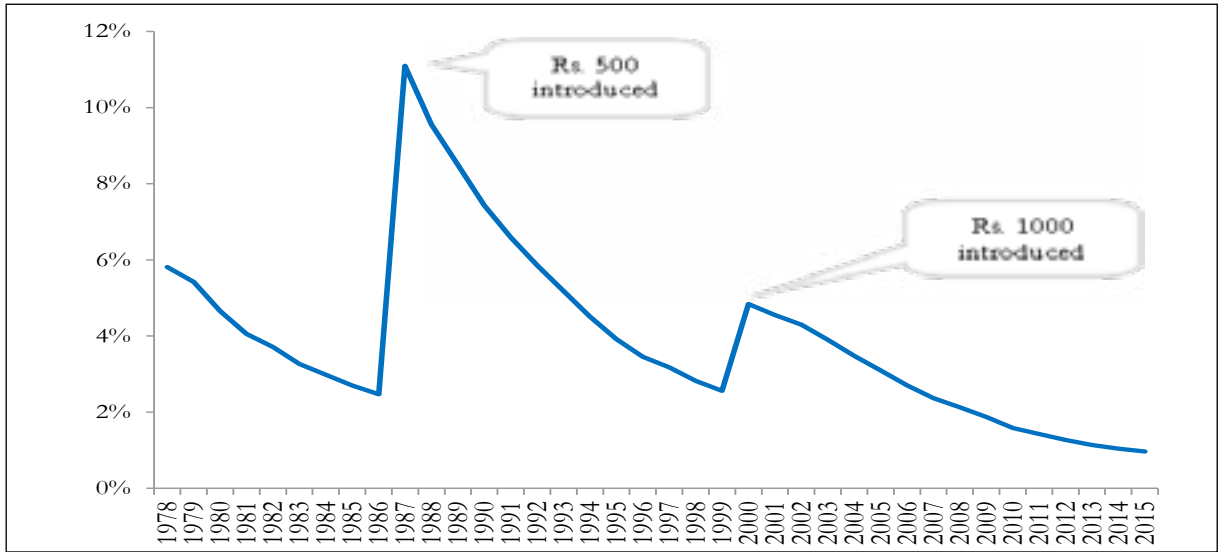
स्रोत : ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल : विश्व विकास सूचक

के 'मैले हो जाने' की दर हैं। अर्थात् लेनदेन की वह दर जिस पर नोटों इतने गंदे घोषित हो जाते हैं कि बैंक उन्हें ग्राहकों को देने के स्थान पर केंद्रीय बैंक के पास लौटा देना बेहतर समझते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि निम्न मान के नोटों के मैले होने की दर 33 प्रतिशत प्रतिवर्ष है, रू. 500 के नोटों की 22 प्रतिशत तथा रू. 1000 नोटों की यह दर तो मात्रा 11 प्रतिशत रही है। कालेधन के आंकलन की एक

संभावित विधि है : यदि सभी नोटों का सामान्य रूप से लेनदेन में प्रयोग होते हैं तो उनके मैले हो जाने की दर भी समान प्रायः होनी चाहिए। अतः हमें लेनदेन में अप्रयुक्त मुद्रा का एक अनुमान मिल जाता है : यह है रू. 7.3 लाख करोड़।

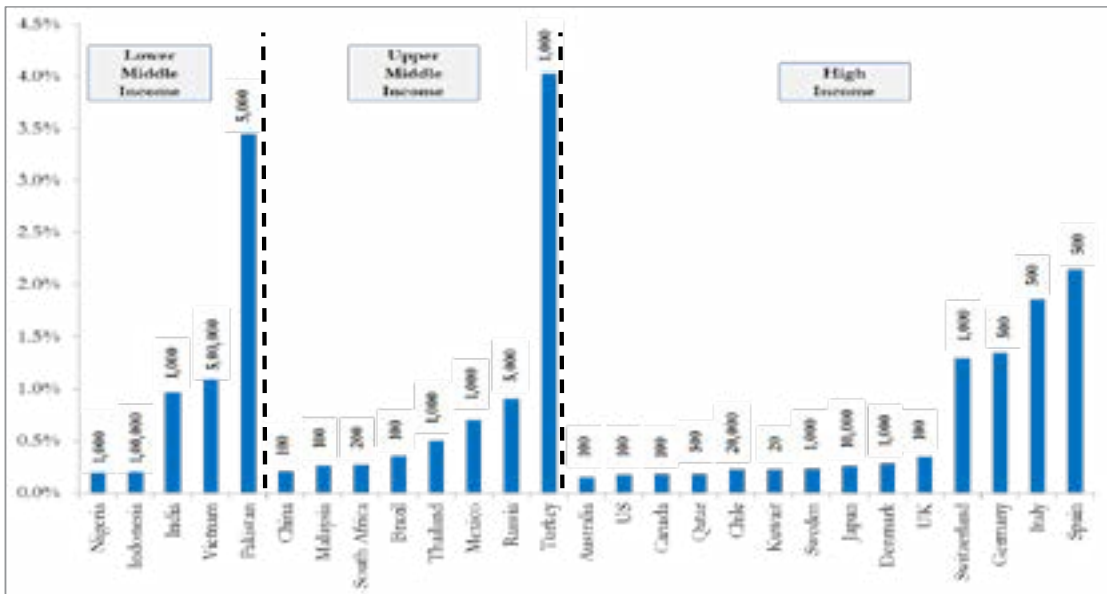
3.21 किन्तु इस मान्यता को पूर्णतः स्वीकार कर लेना कुछ अनुचित रहेगा। बड़े नोटों के मैले होने की

रेखाचित्र 5 : उच्च नोटमान/आय अनुपात (प्रति व्यक्ति जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत : विश्व विकास सूचक; भारतीय रिजर्व बैंक

रेखाचित्र 6 : उच्चतम मान नोट (जीडीपी प्रतिव्यक्ति के प्रतिशत के रूप में)



स्रोत : केन्द्रीय बैंकों के तुलनपत्र, विश्व विकास सूचक

दर इस कारण से भी कम रह सकती है कि बड़े नोटों की जरूरत पड़ने वाले लेनदेन कम होते हैं।

3.22 किन्तु इन दो धारणाओं के बीच अंतर करने की एक विधि है तो, भले ही उसे संपूर्ण नहीं माना जाए। हम भारत के आंकड़ों की अन्य देशों में मैला पड़ने की दरों की तुलना कर सकते हैं। सिद्धांत रूप में रूपए के नोट और विदेशी करेंसी के नोट एक जैसे लेनदेन संपन्न करते हैं तो उनके मैले पर जाने की दरें भी समान प्रायः होनी चाहिए। यदि भारत की यह दर कम हो तो संकेत मिलेगा कि संभवतः उन नोटों का एक अंश लेनदेन के लिए नहीं बल्कि कालाधन जमा करके रखने में काम आ रहा होगा।

3.23 यदि अमेरिका के \$20 और \$50 के नोटों के मैला पड़ने की दर का प्रयोग कर भारत के उच्च मान नोटों का आंकलन करे तो लेनदेन में प्रयुक्त नहीं होने वाली मुद्रा का मान रू. 3 लाख करोड़ बनता है। यह राशि भी बहुत अधिक है। यह जीडीपी के 2 प्रतिशत के समान है।

III. विश्लेषण विधि

3.24 विमुद्रीकरण के लाभ और लागतों को समझने के लिए इसकी विश्लेषण विधियों का विस्तार आवश्यक है, यह कार्य बहुत ज्ञानवर्धक एवं जटिलतापूर्ण है। मोटेतौर पर, कई प्रभाव होंगे। उन प्रभावों का निरूपण तालिका-2 में किया जा रहा है।

3.25 विश्लेषणात्मक पटल पर विमुद्रीकरण के ये घटक दृष्टिगोचर होने चाहिए :

- मुद्रा की आपूर्ति में संकुचन, किन्तु केवल एक प्रकार की, अर्थात् नकद मुद्रा में
- अघोषित निजी संपत्ति (नकद रखी गई) या कालेधन पर कर
- औपचारिक वित्त व्यवस्था से बाहर रखी गई बचतों पर कर

3.26 हम मुद्रा आपूर्ति में संकुचन के प्रभावों (जो क्षणिक ही रहने वाले हैं) पर बाद में चर्चा करेंगे। पहले तो हितलाभों पर ध्यान दे रहे हैं।

IV. हितलाभ

(क) कालेधन पर कर

3.27 यह संभवतः विमुद्रीकरण की व्याख्या की सबसे महत्वपूर्ण विधि है, इसे ऐसा कर प्रशासन कदम माना जा सकता है जो कालेधन पर एक कर की भांति है। यह सत्य है कि केवल बड़े नोटों का विमुद्रीकरण कालेधन के विमुद्रीकरण के समान नहीं है। कुछ नकद कोष निश्चित रूप से कालाधन नहीं थे, ये ऐसी आय से बचाकर रखी गई राशियां थीं जिनपर कर चुकाया जा चुका था या कृषि जैसे स्रोतों से अर्जित आय थी जिस पर कोई कर देय नहीं होता।

3.28 अतः सारी कार्ययोजना में एक समीक्षा विधि सम्मिलित रही, वह कालेधन और सफेद धन को अलग करने के लिए बनाई गई थी। घोषित आय में से नकदी के रूप में रखी बचत को बैंक में जमा कराया जा सकता था और उसके बदले नए नोट प्राप्त किए जा

तालिका 2. विमुद्रीकरण का प्रभाव

क्षेत्रक	प्रभाव	
	दिसंबर अंत तक प्रभाव	संभावित दीर्घकालिक प्रभाव
मुद्रा/ब्याज की दर	नकदी में भारी कमी बैंक जमाओं में तीखी वृद्धि रिजर्व बैंक का तुलनपत्र प्रायः अप्रभावित : करेंसी वापसी से केंद्रीय बैंक की नकद देनदारी में कमी किन्तु इसकी व्यापारिक बैंकों के प्रति जमा देनदारियों में वृद्धि जमाओं, ऋणों और सरकारी निक्षेपों पर ब्याज दर में कमी, नकद पर निहित दर में वृद्धि	नकदी में वृद्धि होगी, किन्तु यह पूर्ववर्ती से निम्न स्तर पर ही रहेगी जमाएँ कम होंगी, किन्तु पहले से उच्च स्तर पर ही रहेगी व बैंक का तुलनपत्र संकुचित होगा (बचे हुए पुराने नोट बदलने की तिथि के बाद) ऋणों पर दरें और कम होंगी, यदि जमाओं की वृद्धि का स्वरूप स्थायी रहा
वित्त व्यवस्था की बचतें	वर्धित होंगी	नकद जमा अनुपात में स्थायी गिरावट के अनुसार वृद्धि
भ्रष्टाचार (गैरकानूनी कार्यों में निहित)		यदि अनुपालन की प्रेरणाएं बलवती हुई तो भ्रष्टाचार में गिरावट होगी

अघोषित आय/ कालाधन (इसका आधारभूत कार्य भले ही गैरकानूनी नहीं हो)	कालेधन के भंडार में कमी, कुछ कालाधनधारी कर पाश में फंसे	औपचारिकरण से अघोषित आय का प्रवाह कम होगा
निजी संपत्ति	निजी क्षेत्र की संपत्ति में गिरावट, कुछ उच्चमान नोट लौटाए नहीं गए, भवन संपदा कीमतों में गिरावट	यदि भवन संपदा कीमतों में गिरावट चलती रही तो निजी धन और कम होगा
सार्वजनिक क्षेत्र की संपत्ति	कोई प्रभाव नहीं हुआ	सरकार/RBI के धन में बिना लौटाए गए नकद के समापन से वृद्धि होगी, देनदारियां कम होगी
औपचारिकरण/ डिजिटलईजेशन	नए प्रयोक्ताओं में RuPay/AEPS के प्रयोग में तीखी वृद्धि, वर्तमान प्रयोक्ताओं द्वारा इनका प्रयोग पूर्ववत् चलता रहा	कुछ व्यक्ति नकदी की आपूर्ति बढ़ने पर पुनः नकद प्रयोग करने लगेंगे, किन्तु डिजिटल क्रांति जारी रहेगी।
भवन संपदा	कीमतें कम हुई, धन में गिरावट, नकदी के अभाव में लेनदेन कम हुआ	अघोषित आय का भवन संपदा में निवेश कठिन होने से कीमतें कम हो सकती हैं, यदि इन संपदाओं पर जीएसटी लगा तो कर का अंश और अधिक हो जाएगा
बृहतर स्तर पर अर्थव्यवस्था	रोजगार स्तर में कमी, कृषि आय में कमी, सामाजिक असंतोष, विशेषकर नकद सघन क्षेत्रों में	पुनः मुद्रिकरण होने के साथ-साथ इनमें स्थिरता पुनः स्थापित हो जाएगी
जीडीपी	संवृद्धि में शिथिलता, विमुद्रीकरण ने नकदी और निजी संपत्ति में कमी के माध्यम से मांग में कमी की है, तरलता और काम चलाऊ पूँजी घटा कर और माल असबाब की आपूर्ति श्रृंखला को भंगकर सकल आपूर्ति में कमी की है। साथ ही अनिश्चितता अधिक हा गई है। कृषि, भवन संपदा, आभूषण जैसे नकद प्रधान क्षेत्रों में हानि अधिक रही जीडीपी के आंकड़े अनौपचारिक क्षेत्र पर पड़े 'नकारात्मक' प्रभावों को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाएंगे, कारण यही है कि प्रायः औपचारिक क्षेत्र के उत्पादन के एक अंश के रूप में अनौपचारिक के लिए अनुमान गढ़ लिया जाता है। किन्तु जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था में औपचारिकरण में वृद्धि होगी, यह अधोअनुमान भी कम हो जाएगा। जीडीपी के दर्ज किए गए आंकड़े इस कारण भी अधिक होंगे कि बैंक क्षेत्र में मूल्यवृद्धि का आंकलन तो जमा राशियों के आधार पर करते हैं, तथा पुराने नोट बैंकों में जमा हो गए हैं। यह उछाल भी अस्थायी ही है।	यदि औपचारिकरण में दीर्घकालिक स्तर पर वृद्धि हुई और भ्रष्टाचार कम हुआ तो इससे लाभ ही होंगे। अनौपचारिक क्षेत्र के उत्पादन में कमी के बावजूद औपचारिकरण की वृद्धि से जीडीपी में सुधार ही दिखाई देगा।
कर संकलन	अधिक आय की घोषणा के कारण आय कर में वृद्धि हुई है। कर जमा कराने और बकाया का भुगतान करने के लिए पुराने नोट मान्य रहे। अतः स्थानीय निकायों तथा वितरण संस्थानों को भुगतानों में वृद्धि दिखाई दे सकती है।	संवृद्धि की शिथिलता से अप्रत्यक्ष और निगम कर संग्रह कम हो सकते हैं। औपचारिकरण में सुधार और कर अनुपालन में वृद्धि से दीर्घकालिक पटल पर कर संग्रह अधिक होगा।
अनिश्चितता/ विश्वस्तता	अनिश्चितता में वृद्धि हुई है, फर्मों और परिवार, दोनों में ही आर्थिक प्रभावों और भावी नीतियों पर प्रभावों को लेकर असमंजस फैला है। निवेश एवं स्थायी प्रयोग की चीजों की खरीदारी स्थगित हुई है	यदि विमुद्रीकरण के अनुषांगिक कदम उठाए गए तो विश्वस्तता में सुधार होगा। शीघ्र एवं पूर्ण पुनःमुद्रिकरण अनिवार्य है। कर निर्धारण में मनमानी और करदाता वर्ग का उत्पीड़न सरकार की विश्वस्तता के लिए घातक हो सकते हैं।

सकते थे। किन्तु कालेधन के स्वामियों के समक्ष तीन 'कठिन' विकल्प थे। ये संभव थे :

- अपनी आय घोषित करें और उस पर दंडात्मक कर भरें;
- उसे छुपाए रहें, नए नोटों में नहीं बदलवाएं और इस प्रकार शत प्रतिशत दर पर कर चुकाएं; और
- अपने कालेधन को 'परिवर्तन लागतें' उठाकर सफेद कर लें।

3.29 दृश्यांत रूपी साक्ष्य यही सुझाते हैं कि तीसरी विधि, कालेधन की 'धुलाई' द्वारा उसके 'श्वेतीकरण' का कार्य खूब किया गया। एक ऐसा तरीका तो आय की प्राप्ति के समय की परिवर्तन रहा, ऐसी रसीदें गढ़ी गईं जिनसे लगे कि यह तो अभी-अभी 8 नवंबर 2016 से तुरंत पहले कमाई गई राशियां हैं। ऐसे तकनीकों कालेधन को बैंकों में जमा करा सकती थी, किन्तु कर चुका कर। इस प्रकार कालाधन कर पाश में आ जाता।

3.30 अन्य तकनीकों में कालेधन के स्वामियों को अपना धन सफेद करने के लिए बिचौलियों को कुछ न कुछ अंश भाग देना पड़ता था। उदाहरण: कुछ व्यक्तियों ने अन्य लोगों को बैंक की लाइनों में खड़े होकर नोट बदलवाने या जमा कराने के लिए पैसे दिए थे। यह भी बड़े पैमाने पर देखा गया कि जनधन खातों में नवंबर 8 से दिसंबर 30 की 50 दिनों अवधि में बहुत "भारी" राशियां जमा कराई गईं। हां यह कुल राशियां अपेक्षाकृत कम ही रही, केवल रू. 42000 करोड़।⁸

3.31 इन सभी मामलों में कालेधन वालों को एक बड़ा घाटा अवश्य उठाना पड़ा, चाहे उन्होंने कर भरा या नकद बदलने का कमीशन चुकाया। यही नहीं, अभी उन बैंक खातों को खंगाला जा रहा है, जिनमें संदेहास्पद लेनदेन हुए हैं, अर्थात् जिन्होंने बैंको में जमा कराने के माध्यम से धन की धुलाई की है, उन पर अभी तक चुकाई गई फीस और करों के अतिरिक्त दंडात्मक कर एवं अभियोजन की तलवार लटक रही है।

3.32 हां, कुछ पुराने नोट वापस नहीं हुए। दिसंबर 30, 2016 के एक अध्यादेश ने ऐसे नोटों को अवैध घोषित कर दिया है। इनका अब किसी लेने में प्रयोग

संभव नहीं रहा। जब नियत रियायत अवधि समाप्त होगी तो ये नोट किसी भी प्रकार से नए नोटों में परिवर्तनीय नहीं रहेंगे। ऐसा होने पर उक्त नोटों से जुड़ी रिजर्व बैंक की देयताएं भी समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से विमुद्रीकरण ने कालेधन स्वामियों की धन राशियों का सार्वजनिक क्षेत्र को अंतरण कर दिया है। अब इनका प्रयोग अनेक उत्पादक कार्यों में हो सकेगा : सरकारी ऋण चुकाने में, बैंकों के पुनःपूंजीकरण में, या निजी क्षेत्र को पुनःवितरण में भी।

3.33 अधिक सटीक रूप से कहें तो नहीं लौटाए गए पुराने नोट गैर कानूनी धनस्वामियों से छीन कर लगाए जाने का कोई विश्वस्त अनुमान नहीं दे सकते। इनके साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत घोषित आय पर चुकाए गए करों तथा धन की धुलाई करने वाले मध्यस्थों को चुकाए गए शुल्क कमीशन आदि का जोड़ भी किया जाना चाहिए।

(ख) कर अनुपालन

3.34 विमुद्रीकरण को सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन भी कहा जा सकता है। यह कालेधन पर आघात के सरकारी निश्चय का प्रतीक एवं प्रमाण है, यह दिखाता है कि अब करवंचना को जीवन की एक जरूरी विवशता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस कदम को जनता का व्यापक समर्थन मिला है। अतः स्पष्ट है कि समाज का जनसामान्य भी कालेधन को सहन करने के लिए तैयार नहीं है।

3.35 इन दो अनुशस्तियों, वित्तीय दंड और सामाजिक भर्त्सना, के बहुत सशक्त एवं दीर्घकालिक प्रभाव हो सकते हैं। विशेषकर उस समय जब इन्हें अनुच्छेद X में वर्णित संप्रेरणा संगत कदमों का समर्थन भी मिल जाए। उस स्थिति में कर वंचक यही निर्णय करना बेहतर समझ सकते हैं कि एक सामान्य दर पर कर भरना अचानक सबकुछ खो देने से कहीं अच्छा होगा। इससे भ्रष्टाचार और कर अनुपालन पर स्थायी प्रभाव पड़ेगा।

3.36 विमुद्रीकरण एक अन्य प्रकार से भी कर प्रशासन की सहायता कर सकता है। यह लेनदेन को नकद तंत्र से औपचारिक भुगतान तंत्र की ओर उन्मुख कर सकता है। बड़े नोट बंद होने पर परिवार और फर्म अब नकदी

⁸ यह आंकड़ा नवंबर 10 से दिसंबर 23, 2016 के बीच है है। देखें <http://www.hindustantimes.com/india-news/jan-dhan-accounts-deposits-double-to-rs-87-000-crore-i-t-dissects-data/stor y-Nf4iM7X8byNglVo8okVaN.html>

को छोड़कर इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तकनीकों का अधिक प्रयोग करने लगे हैं।

3.37 परिणाम स्वरूप कर जीडीपी अनुपात और औपचारिक अर्थव्यवस्था में स्थायी वृद्धि हो सकती है।

(ग) अनौपचारिक बचतों पर कर

3.38 कर वंचना के अतिरिक्त भी विमुद्रीकरण के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह बचतों को औपचारिक वित्त व्यवस्था में प्रवाहित करेगा। निःसंदेह, बैंकों में जमा कराई गई अधिकांश नकदी जैसे ही नोटों की आपूर्ति में सुधार होने पर आहरण की सीमा बढ़ाई जाएगी, निकाल ली जाएगी। किन्तु इन जमाओं का कुछ अंश अवश्य बैंक खातों में ही जमा रह जाएगा। यह अंश बैंकों द्वारा अधिक साख मुद्रा (उधार) प्रदान करने का आधार बनेगा, वह भी अपेक्षाकृत कम ब्याज दर पर।

3.39 दीर्घकालिक रूप से, यदि विमुद्रीकरण सफल रहा तो यह अर्थव्यवस्था में नकद जीडीपी और नकद जमा अनुपातों को कम कर देगा। इससे वित्तीय बचतों की वृद्धि होगी और उसका दीर्घकालिक संवृद्धि पर एक सकारात्मक प्रभाव होगा।

V. संभावित दीर्घकालिक हितलाभ के प्रारंभिक साक्ष्य

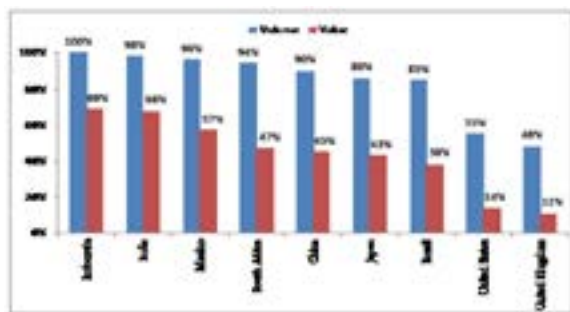
3.40 दीर्घकालिक परिवर्तनों के दिशा एवं परिमाण का सटीक निर्धारण करने के लिए तो अभी, परिभाषा के अनुसार ही, पर्याप्त समय व्यतीत नहीं हुआ है। गैर कानूनी लेनदेन, कालेधन और वित्तीय बचतों पर इस विमुद्रीकरण का सही प्रभाव जानने में तो कई वर्ष लग जाएंगे। फिर भी कुछ संकेत उभर रहे हैं जो परिवर्तन के सूचक हैं।

(क) डिजिटलाइजेशन

3.41 विमुद्रीकरण का एक मध्यकालिक उद्देश्य नकदहीन या नकदक्षीण अर्थव्यवस्था की रचना कर अधिक बचतों को औपचारिक वित्त व्यवस्था में प्रवाहित करना और (इस प्रकार) कर अनुपालन के स्तर को सुधारना था। अभी तो भारत इस उद्देश्य की संपूर्ति से बहुत दूर है। वटाल समिति ने अभी अनुमान लगाया है कि उपभोक्ता वर्ग द्वारा किए जा रहे 78 प्रतिशत

भुगतान तो नकद राशियों में होते हैं।⁹ प्राईस वाटर हाउस कूपर्स की 2015 की रिपोर्ट ने भी कहा था कि भारत में उपभोक्ताओं के लेनदेन में अन्य देशों की तुलना में नकदी की भारी प्रबलता है। यह मूल्यानुसार 68 प्रतिशत है तो संख्यानुसार 98 प्रतिशत (देखें रेखाचित्र-7)। इस स्थिति के कई कारण हैं। नकदी के कई फायदे होते हैं : यह सुविधाजनक है, प्रत्येक स्थान पर स्वीकार्य है और इसका प्रयोग भले ही समाज के लिए लागतहीन नहीं हो किन्तु जन सामान्य के लिए तो इसकी लागत शून्य ही होती है। नकद लेनदेन में किसी का नाम नहीं आता, गोपनीयता बनी रहती है। जब तक यह लेनदेन गैरकानूनी या करवंचना के ध्येय से नहीं हो, ये दोनों ही बातें सद्व्यवस्था होती हैं।

रेखाचित्र 7 : उपभोक्ताओं द्वारा नकद लेनदेन (प्रतिशत, 2015)



स्रोत : प्राईस वाटरहाउस कूपर्स, 2015

3.42 इसके विपरीत डिजिटल लेनदेन में कई बाधाएं उपस्थित रहती हैं। इनके लिए विशेष उपकरणों की आवश्यकता होती है। उपभोक्ता को सैलफोन तो विक्रेता को विक्रय-बिन्दु मशीन चाहिए। ये दोनों उपकरण तभी काम करेंगे जब इंटरनेट से संपर्क हो। ये भुगतान विधि लागत भरी भी है, क्योंकि ई-भुगतान फर्मों को अपनी लागतें पूरी करने के लिए भुगतान सेवा ग्राहकों-विक्रेताओं या दोनों पर भी शुल्क लगाने पड़ते हैं। हां, कुछ निर्विवाद सत्य इन बाधाओं की क्षतिपूर्ति भी कर देते हैं। डिजिटल लेनदेन जनता को आधुनिक “तार संपर्क” युग से जोड़ देते हैं। वह जनता को औपचारिक वित्ततंत्र से जोड़कर सक्रिय वित्तीय बचत संकलन को बढ़ावा भी देता है। इससे कर वंचना कम होती है और कर-अनुपालक एवं कर वंचक फर्मों और व्यक्तियों के बीच की खाई कम हो जाती है।

⁹ http://www.finmin.nic.in/report/watal_report271216.pdf

3.43 डिजिटलाइजेशन का मोटेतौर पर समाज के तीन वर्गों पर प्रभाव होगा : गरीबजन, जो अभी तक पूरी तरह डिजिटल अर्थतंत्र से असंबंधित है; कम समृद्ध, जो जनधन खाता और RuPay कार्डों के माध्यम से डिजिटल अर्थतंत्र से जुड़ते जा रहे हैं; और धनी वर्ग जो पहले से ही अपने क्रेडिट-डेबिट कार्डों के माध्यम से पूरी तरह डिजिटल तंत्र से संबंधित है। इन तीन वर्गों के आकार की ओर संकेत करने वाला एक सरल सा सूचक सैलफोन का स्वामित्व है। देश में 350 मिलियन व्यक्ति सैलफोन से रहित है; 350 मिलियन के पास सामान्य “फीचर” फोन हैं; तथा 250 मिलियन के पास स्मार्ट फोन हैं।

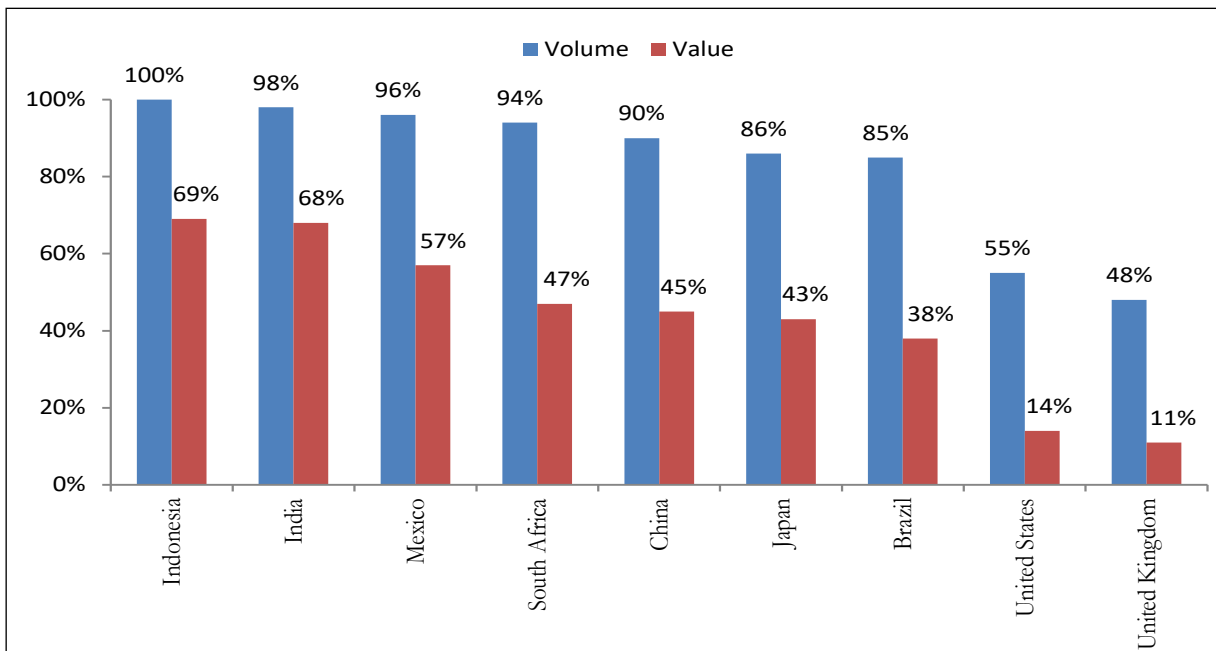
3.44 विमुद्रीकरण के बाद से सरकार ने जनता को डिजिटल अर्थतंत्र की ओर उन्मुख करने के लिए कई सुविधाएं और प्रोत्साहन दिए हैं। इनमें शामिल हैं :

- भीम - ‘भारत इंटरफेस फॉर मनी’ नामक स्मार्टफोन ऐप। यह नवीन एकीकृत भुगतान इंटरफेस (UPI) पर आधारित है और विभिन्न डिजिटल लेनदेन प्लेटफॉर्मों के बीच संपर्क साधने में समर्थ है। जनवरी 10 तक 10 मिलियन प्रयोक्ता इसे अपने सैलफोन में डाउनलोड कर चुके थे। एक मिलियन से अधिक भुगतान/लेनदेन भी इसके माध्यम से हो चुके थे। अब 250 मिलियन स्मार्टफोन स्वामी तो

बड़ी सरलता से तुरंत भुगतान कर सकते हैं।¹⁰

- भीम यूएसएसडी 2.0, वह उत्पाद है जो ‘फीचर फोन’ पर भी UPI का लाभ संभव बनाता है। इसके माध्यम से अब 350 मिलियन “फीचर फोन” प्रयोक्ताओं को भी यह क्षमता प्रदान हो चुकी है।
- ‘आधार विक्रेता भुगतान’ व्यवस्था का प्रारंभ कर शेष 350 मिलियन फोन रहित उपभोक्ता भी अब डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। अब कोई भी बैंक खाताधारी अपने आधार नंबर का प्रयोग कर अपने अंगूठे के निशान के सत्यापन के माध्यम से विक्रेता को भुगतान कर सकता है। आधार भुगतान को शीघ्र ही भीम से जोड़कर एक उपयुक्त प्रकार के विक्रय-बिन्दु उपकरण शीघ्र ही बाजार में लाने का कार्य चल रहा है।
- डिजिटल एवं UPI आधारित भुगतानों की विक्रेता से उगाही जा रही फीस में कटौतियां हो रही हैं। ‘भुगतान वैले’ के प्रयोग पर लगी सीमाएं भी उदार की जा रही हैं। डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए करों में भी कुछ छूट दी जा रही है।
- शुल्क कटौती के माध्यम से विक्रय-बिन्दु उपकरणों का प्रयोग वर्तमान 1.5 मिलियन से बढ़ाने की ओर कदम उठाए जा रहे हैं।

रेखाचित्र 7 : उपभोक्ताओं द्वारा नकद लेनदेन (प्रतिशत, 2015)



¹⁰ इस एप ने विक्रेताओं के लिए मानक विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर कार्यक्षम UPI-IQR का ही प्रयोग किया है।

3.45 अभी RuPay और भुगतान बटुआ सुविधाएं डिजिटल लेनदेन के बहुत ही संक्षिप्त भाग की समानता कर पा रही हैं। कुल वित्तीय लेनदेन की अपेक्षा भी इनका परिमाण बहुत ही कम है। उदाहरण के लिए दिसंबर का रिजर्व बैंक का भुगतान सर्वेक्षण बता रहा है कि डिजिटल बटुओं से 95 बिलियन रूपयों का भुगतान हुआ, और UPI से मात्र 7 बिलियन का, जबकि डेबिट कार्डों से (RuPay और ATM को छोड़कर) 314 बिलियन रूपयों और क्रेडिट कार्डों से 270 बिलियन रूपयों के भुगतान हुए हैं। किन्तु इन नई सुविधाओं का प्रयोग निरंतर वृद्धिशील है।

3.46 आधार आधारित भुगतान व्यवस्था (AEPS) द्वारा लेनदेनों से हम अभी तक डिजिटल तंत्र से बाहर रहे समुदायों पर प्रभाव का आकलन कर सकते हैं। हमने पाया है कि AEPs लेनदेनों में नवंबर 8, 2016 से पहले भी वृद्धि का क्रम चल रहा था, परन्तु उस तिथि के बाद इस वृद्धि में और तेजी आई है (रेखाचित्र 8'क')।

3.47 डिजिटल संपर्क के मध्यम वर्ग पर प्रभाव की झलक RuPay लेनदेनों से मिल जाती है। राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़े बता रहे हैं कि विक्रय-बिन्दुओं पर लेनदेन में ₹. 13000 करोड़ तथा ई-कॉमर्स में ₹. 2000 करोड़ की वृद्धि हुई है। यह 300-400 प्रतिशत की वृद्धि रेखाचित्र 8ख में अंकित है।

3.48 क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड लेनदेन डिजिटल तंत्र

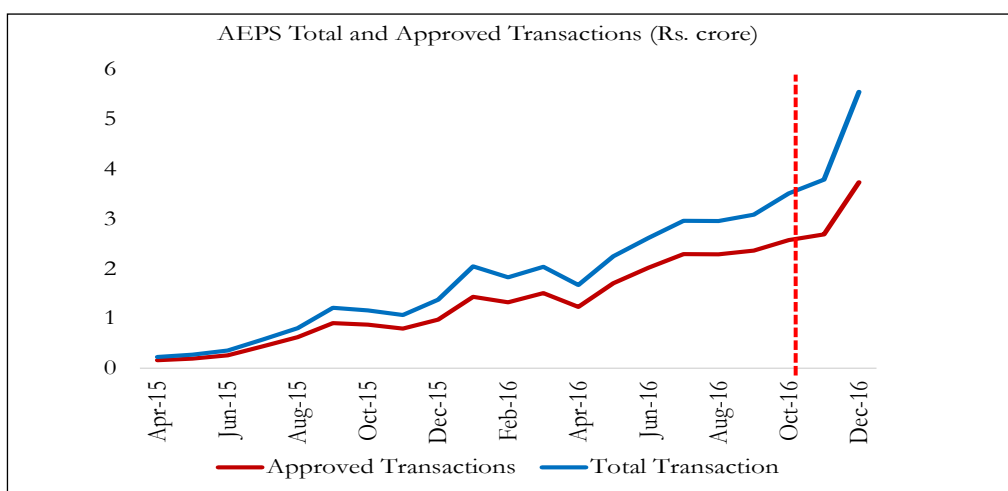
से जुड़े समृद्ध वर्ग के विषय में जानकारी दे रहे हैं (RuPay तथा ATM निकासी पर तो नकदी के अभाव का प्रभाव पड़ा था, अतः उन लेनदेनों को छोड़कर ही हम यहाँ आंकलन कर रहे हैं (रेखाचित्र 8ग))। नवंबर 8, 2016 के बाद इनमें 21 प्रतिशत की तीखी वृद्धि हुई है। हाँ यह देखना है कि क्या पुनः मुद्राकरण के बाद भी यह प्रवृत्ति चलती रहेगी। UPI लेनदेनों में भी भारी वृद्धि दिखाई दे रही है, किन्तु उसका प्रारंभिक स्तर बहुत ही नगण्य प्रायः था।

3.49 जैसे-जैसे लोगों ने इन ई-भुगतान विधियों का प्रयोग करना आरंभ किया है, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक विधि से वित्तीय कार्य करने की सुविधा भी समझ आने लगी है। उन्हें अब पता चल रहा है कि इस प्रकार भुगतान की सुविधा तो बहुत से स्थानों पर सफल है। विमुद्रीकरण इस तंत्र को और विकसित कर रहा है। जैसे-जैसे कोई पहल करने वाला व्यक्ति इस में पारंगत होता है, उसके अनुकरण से और अनेक व्यक्ति इस तंत्र से जुड़ जाते हैं। अधिक परिवारों की भागीदारी और ज्यादा फर्मों को इससे जुड़ने को प्रोत्साहित कर रही है। किन्तु फिर भी, ई-भुगतान तंत्र के सुरक्षा पक्षों को और सुदृढ़ करना जरूरी है। तभी इनमें और विश्वास जागृत होगा।

(ख) भवन संपदा

3.50 भवन-संपदा क्षेत्रक पर तो विमुद्रीकरण का प्रभाव विशेष रूप से अधिक गहरा होने की अपेक्षा

रेखाचित्र 8क : डिजिटल तंत्र से बाहर रहे समुदाय द्वारा डिजिटल भुगतान (करोड़ रूपए)

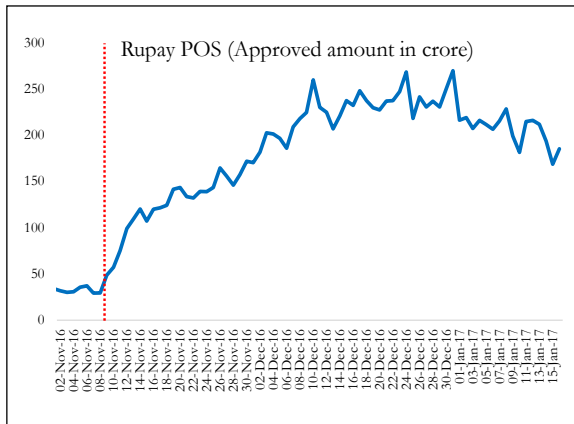


स्रोत : NPCI

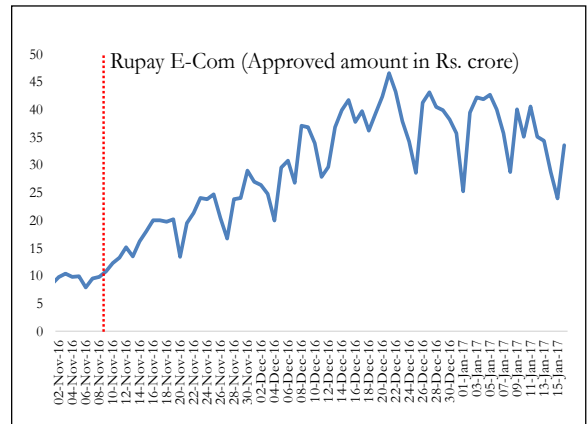
नोट : आधार आधारित भुगतान व्यवस्था

रही है। अतीत में अधिकांश कालेधन का सृजन (और उसकी खपत भी) संपत्ति के लेनदेन में ही कर वंचना के ध्येय से होता रहा है। जैसे कालेधन में कमी होगी, और वित्तीय लेनदेन इलैक्ट्रॉनिक विधि से होने लगेगा, यह कर वंचना भी निर्यात्रित हो जाएगी। अभी यह कहना तो जल्दबाजी होगी कि यह प्रभाव कितना स्थायी रहेगा, हमारा रेखाचित्र-10 यही दर्शा रहा है कि 8 बड़े नगरों में भवन संपदा का भारित औसत सूचक, जो पहले से ही हासमान था, 8 नवंबर के बाद और तेजी से कम हुआ है। भवन संपदा कीमतों में एक संतुलनकारी गिरावट आवश्यक है, तभी मध्यमवर्ग को (उचित दाम पर) अपने घर का सपना पूरा करने का अवसर मिल पाएगा। इससे अन्ततः किराए भी कम होंगे और अभी तक बाधित श्रम की गतिशीलता में भी सुधार होगा।

रेखाचित्र 8ख : दैनिक डिजिटल लेनदेन (करोड़ रूपए) : कम समृद्ध उपभोक्ता वर्ग

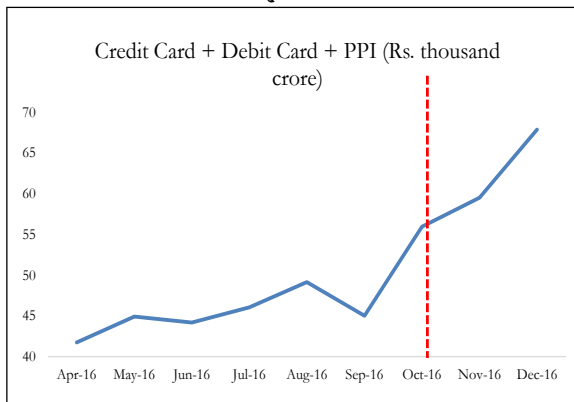


स्रोत : NPCI



स्रोत : NPCI

रेखाचित्र 8ग : मासिक डिजिटल लेनदेन समृद्ध वर्ग

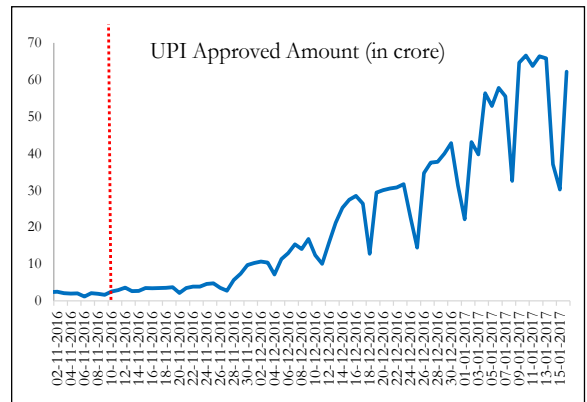


स्रोत : NPCI

नोट : PPI – पूर्व भुगतान उपस्कार

डेबिट कार्ड लेनदेन से ATM और RuPay लेनदेन घटा दिए गए हैं।

रेखाचित्र 8घ : दैनिक डिजिटल लेनदेन UPI द्वारा



स्रोत : NPCI

VI. अल्पकालीन प्रभाव

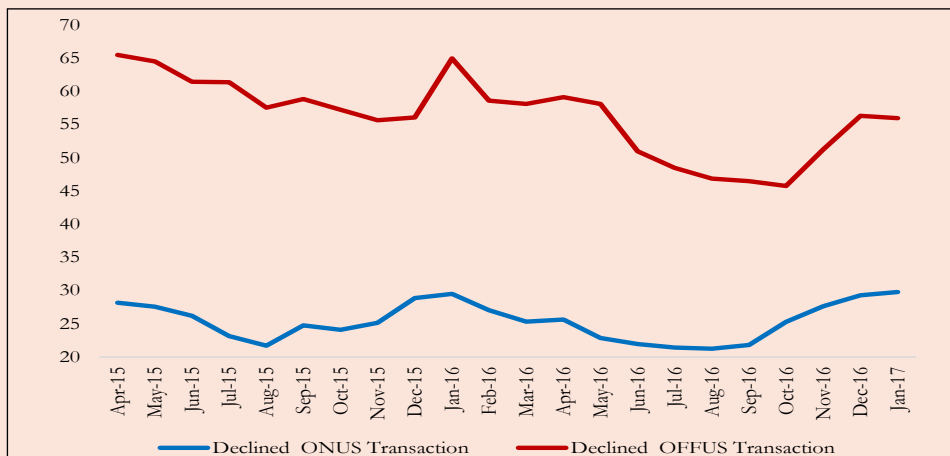
3.51 दीर्घकालिक सकारात्मक प्रभावों की बहुत संभावनाएं अपने स्थान पर हैं, किन्तु विमुद्रीकरण की कुछ अल्पकालिक लागतें तो समाज को सहनी ही पड़ेंगी। उन लागतों के स्तर का अनुमान लगा पाना भी अभी तो कठिन ही है, क्योंकि विभिन्न क्षेत्रों से जानकारी अभी आनी प्रारंभ ही हुई है। दूसरे अर्थव्यवस्था का आकार इतना विशाल एवं विविधतापूर्ण है कि केवल कुछ सूचकों के आधार पर समस्त अर्थव्यवस्था के विषय में किसी निष्कर्ष का निष्पादन एक बहुत ही जोखिम भरा कार्य सिर्फ होगा। वैसे भी विमुद्रीकरण एक इतना बड़ा संरचनात्मक संक्षोभ है कि पुराने व्यवहार प्राचल तो भावी व्यवहार के बहुत अपूर्ण सूचक बनकर यह जाएंगे। फिर

बॉक्स-1 : बैंकों को अंतर्प्लेटफॉर्म कार्य बाधित करने से रोकना

डिजिटलाइजेशन की सफलता बहुत सीमा तक भुगतान तंत्र के विभिन्न प्लेटफॉर्मों के बावजूद बाधारहित चलने पर निर्भर करेगी। NPCI द्वारा बनाए गए UPI की प्रौद्योगिकी अंतर्प्लेटफॉर्म संचलन में सहायक होगी। किन्तु इसे सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक बैंक को अपने स्तर पर इस कार्य में सहयोग करना होगा। बाधाएं उत्पन्न करने से बचना होगा।

इस प्रकार की अंतर्प्लेटफॉर्म कार्यशीलता की एक कसौटी तो एक ही बैंक द्वारा जारी एवं प्राप्ति के लेनदेन की असफलता दर की तुलना (यहां के On-US लेनदेन का उद्धरण लिया जा रहा है) उस दर से हो सकती है जो विभिन्न बैंकों के भुगतान देने एवं पाने वालों के बीच होती है (Off-US)। NPCI द्वारा प्रदान आंकड़ों का प्रयोग कर जनवरी 2017 के मध्य आधार आधारित भुगतानों की अस्वीकृति की दरें आंकलित की गई हैं (रेखाचित्र 9)।

रेखाचित्र 9 : आधार माध्यम से भुगतान अस्वीकार करने की दर



स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक

हमारा यह रेखाचित्र है कि Off-US लेनदेनों की विफलता की दर (56 प्रतिशत) On-US की दर से दुगुनी थी।

एक संभावित व्याख्या यह हो सकती है : बड़े बैंक छोटे भुगतानकर्ता बैंकों ग्राहकों के भुगतान को अस्वीकार कर देते हैं और अपने ही ग्राहकों के भुगतान को तुरंत 'स्वीकार' दिखा देते हैं। इसके कुछ वैध कारण भी हो सकते हैं। किन्तु इन समस्याओं का समाधान करना ही होगा, क्योंकि छोटे भुगतान बैंक, दूरसंचार कंपनियां और छोटे बैंक ही तो वित्तीय समाहन की क्रांति का अग्रणी या हरावल दस्ता है। अतः उनका UPI तंत्र से जुड़ाव डिजिटलाइजेशन की प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होगा। यह गरीब वर्ग को इस क्रांति से जोड़ने के लिए तो निर्णायक सिद्ध होगा।

भी, वर्तमान स्थिति का आंकलन करने के लिए एक विश्लेषक रूप रेखा का निर्माण तो अवश्य करना होगा।

3.52 हम पहले नकद प्रभाव का परिमाण निर्धारण करेंगे। वही जीडीपी पर प्रभाव के अनुमान का आधार बनेगा।

(क) नकदी/मुद्रा पर प्रभाव

3.53 जीडीपी पर प्रभाव का आंकलन करने से पूर्व विमुद्रीकरण के नकदी की आपूर्ति पर प्रभाव का निर्धारण कर लेना आवश्यक है। अभी तक हो चुके प्रभावों का अनुमान लगा पाना भी सरल नहीं है, क्योंकि नवंबर 9 से दिसंबर 30, 216 की अवधि में परिचलन में नकदी का प्रभावी स्तर बहुत सीमा तक इन बातों पर निर्भर था।

(क) अभी तक पुराने नोटों का प्रयोग लेनदेन के लिए चल रहा था;

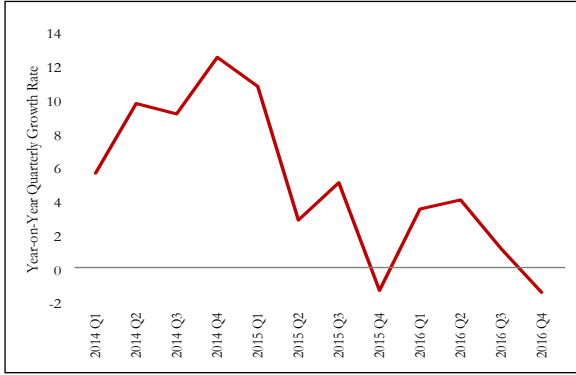
(ख) नए 2000 रूपए के नोट भी 'तरल' मुद्रा थे, व्यक्ति एवं फर्म उनसे लेनदेन कर सकते थे;

(ग) नकदी, पुरानी या नई लौटाई नहीं जा रही थी।

3.54 परिचलन में प्रभावी नकद मुद्रा का आंकलन करने के लिए 'क' और 'ख' के विषय में कुछ और मान्यताएं करनी पड़ेंगी।

- उपर्युक्त 'क' के विषय में यह माना गया है कि 75 प्रतिशत पुराने 500 एवं 1000 रूपए के नोट उक्त अवधि में विधिग्राह्य मुद्रा का कार्य कर रहे थे।
- 'ख' के विषय में मान्यता है कि 2000 रूपए के नए नोटों में से केवल 75 प्रतिशत नवंबर में तरल

रेखाचित्र 10 : भवन संपदा कीमतें



स्रोत : नाइट फ्रैंक और समीक्षा गणनाएं

रहे और दिसंबर में 85 प्रतिशत। जनवरी में जाकर ही (नए 500 रूपए के नोट आने के बाद) ये 100 प्रतिशत व्यवहार में प्रयोग होने लगे थे।¹¹

3.55 दिसंबर अन्त के बाद से प्रक्षेपण करना अधिक सरल है, क्योंकि इसके बाद पुराने नोट सामान्य परिचलन में नहीं रहे थे। यहां तो नए नोटों और उनके मान की आपूर्ति की दर एक निर्णायक चर बन गया था (पुनःमुद्रीकरण)।

3.56 इन सब मान्यताओं और सफलभ जानकारियों के प्रयोग से हम नवंबर 8, 2016 से अप्रैल 2017 के अन्त की अवधि में मुद्रा के प्रभावी परिचलन का अनुमान लगा सकते हैं। ये अनुमान परम रूप में तथा संभावित विनिमय मांग के प्रतिशत अंश के रूप में आंकलित किए गए हैं। यह अंश आंकलन मौद्रिक जीडीपी और डिजिटलाइजेशन के स्तर में वृद्धि तथा नकद जमा अनुपात के संतुलन स्तर में कमी के आंकलन पर आधारित है। यहां भविष्य में नकदी की विनिमय संबंधी कार्यों के लिए मांग में कमी आने की आशा की जा रही है। यह विनिमय मांग अनुमान ही है। इसी कारण हम अपने केन्द्रीय अनुमानों को विश्वस्ति अन्तराल के साथ प्रस्तुत कर रहे हैं (रेखाचित्र 11 'ख')।

3.57 हमारे ये प्रभावी मुद्रा परिचलन के आंकड़े उन संख्याओं से बहुत अलग हैं, जिनका बहुत प्रचार सुनाई दे रहा था।

3.58 प्रचारित आंकड़ों के अनुसार नवंबर 8, 2016 से मासांत तक नकदी में 62 प्रतिशत की कमी हो चुकी

थी। दिसंबर 2016 के अन्त तक यह कमी संकुचित होकर 41 प्रतिशत रह गई थी। किन्तु इनके समतुल्य हमारे आंकड़े तो 25 प्रतिशत और 35 प्रतिशत ही हैं (देखें रेखाचित्र 11(क) और 11(ख))। दूसरे शब्दों में मुद्रा की प्रभावी आपूर्ति में कमी प्रचारित धारणा की अपेक्षा बहुत कम थी और विमुद्रीकरण के वास्तविक मौद्रिक शिखर की प्राप्ति (मनोवैज्ञानिक शिखर से भिन्न) तो नवंबर नहीं दिसंबर 2016 में हो पायी थी।

3.59 प्रभावी आपूर्ति के आंकड़े यह बता रहे हैं कि अब मुद्रा की कमी बड़ी तेजी से समाप्त हो रही है। दिसंबर, 2016 के अंत में प्रभावी मुद्रा कुल मांग के 65 प्रतिशत के समान थी, किन्तु फरवरी 2017 के अंत तक इसके विनिमय मांग के 86 प्रतिशत तक पहुँच जाने की आशा है।

3.60 इन अनुमानों से हम मुद्रा की विनिमय मांग से संबंधित दो प्रकार के मौद्रिक समकों तक पहुँच जाते हैं जो हमें जीडीपी संवृद्धि पर पहुँचने में सहायक हैं। यह हैं परिचलन में नकदी और परिचलन में मुद्रा (नकद तथा मांग जमाओं का योग)। यह माना जा रहा है कि प्रत्येक मास में मांग जमाओं की वृद्धि नए नोटों की निकासी तथा ऋण भुगतान के समंजन बाद पुराने नोटों में जमा कराई गई राशियों के समान है। प्रभावी नकदी और मुद्रा का अनुमान वार्षिक आधार पर इस प्रकार किया गया है :

- वर्ष 2016-17 का उत्तरार्द्ध (औसत) (-)12.5 प्रतिशत नकद और +3.5 प्रतिशत (नकद + मांग जमाएं)
- 2016/17 औसत (+)1.2 प्रतिशत और (+)9.1 प्रतिशत

VII. जीडीपी पर प्रभाव

3.61 सबसे पहले तो विमुद्रीकरण के अल्पावधि संक्षोभ की कार्यविधि को समझ लेना जरूरी है। विमुद्रीकरण संभावी रूप से है :

- **एक सकल मांग संक्षोभ** : क्योंकि यह मुद्रा की आपूर्ति को घटाता है और निजी संपदा (विशेषकर अघोषित धन तथा भवन संपदा के स्वामियों की) को प्रभावित करता है;

¹¹ पुनः उपलब्धता के आधार पर आंकलन है कि 2000 के नए नोट नवंबर 2016 में 14 प्रतिशत, दिसंबर में 35 प्रतिशत, जनवरी में 47 प्रतिशत नकद परिचलन के समान रहे। मार्च 2017 के अंत में पहुँच कर इनका परिचलन घटकर 39 प्रतिशत रह गया।

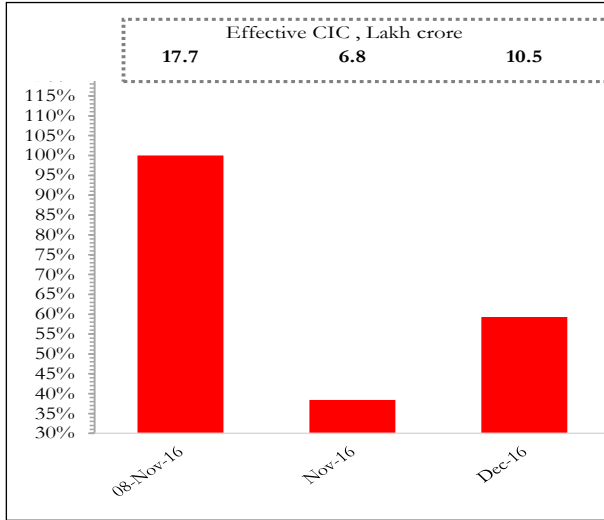
- **एक सकल आपूर्ति संक्षोभ** : जहां तक आर्थिक कार्यों में नकदी एक आदान की तरह प्रयोग होती है (उदाहरण : कृषि उत्पादकों को श्रमिकों की मजदूरी चुकाने के लिए नकद चाहिए) और
- **एक अनिश्चितता रूपी संक्षोभ** : क्योंकि आर्थिककर्ता तरलता संक्षोभ के स्तर और अवधि को लेकर आश्वस्त नहीं होते, साथ ही उन्हें भविष्य में अपनाई जाने वाली नीतियों को लेकर भी संशय हो जाते हैं (उपभोक्ता अपने ऐच्छिक व्यय स्थगित

करने लगते हैं तो फर्म अपनी निवेश योजनाओं पर पुनः विचार करने लगती है)।

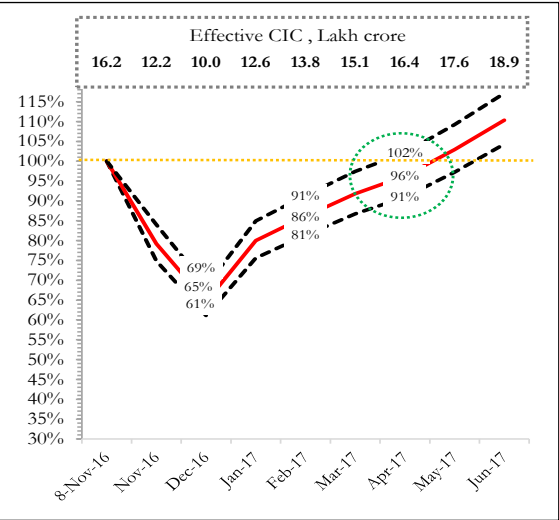
3.62 विमुद्रीकरण के प्रभाव को लेकर तरह-तरह के सर्वेक्षणों और सुने सुनाए किस्सों पर आधारित आंकड़ों की भरमार है। किन्तु हमारी रूचि तो समष्टि स्तरीय समीक्षा में है और इसीलिए हम पांच बृहतर सूचकों पर ध्यान केंद्रित रख रहे हैं :

- रबी की फसल की बुआई
- उत्पादन एवं बिक्री के बड़े सूचक के रूप में अप्रत्यक्ष

रेखाचित्र 11क : प्रभावी करेंसी परिचलन (बाजार की धारणा)



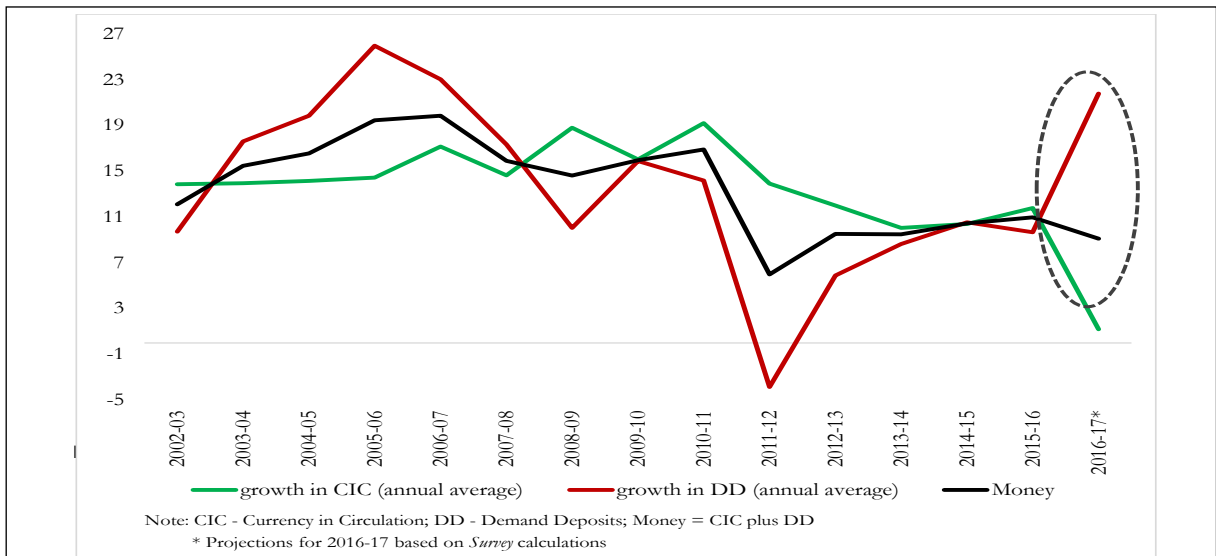
रेखाचित्र 11ख : परिचलन में प्रभावी नकद अनुमानित विनिमय मांग के प्रतिशत के रूप में*



स्रोत : समीक्षा गणनाएं

*यदि कहा न जाए तो मास के अंत में

रेखाचित्र 12 : जनता के पास औसत नकदी तथा मांग जमाएं (प्रतिशत)



स्रोत : समीक्षा गणनाएं

कर राजस्व संकलन;

- वाहनों की बिक्री - यह उपभोक्ता के ऐच्छिक व्यय का अच्छा संकेत देती है। दुपहिया वाहनों की बिक्री कम समृद्ध वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र की ऐच्छिक मांग की सूचक मानी जाती है।
- भवन संपदाओं की कीमतें; और
- वास्तविक साख वृद्धि।

3.63 आशंकाओं के विपरीत जनवरी 15, 2017 तक दो बड़ी फसलों, गेहूं और दालों (चना) की बुआई पिछले वर्ष से क्रमशः 7 तथा 10.7 प्रतिशत अधिक रही (रेखाचित्र 13)। किन्तु इससे उत्पादन में भी समतुल्य वृद्धि हो पाएगी? इसका उत्तर तो इस बात पर निर्भर रहेगा कि विमुद्रीकरण ने किस सीमा तक किसानों की उर्वरक, साख और श्रम जुटा पाने की क्षमता को दुष्प्रभावित किया है।

3.64 उच्च प्रायिकता सूचकों से एक मिला जुला परिदृश्य उभर रहा है (रेखाचित्र 13 से 16)। कृषि बीजाई, यात्रीकारों की बिक्री, और उत्पादन शुल्क के सकल संग्रह पर तो विमुद्रीकरण का कोई प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा। दुपहियों की बिक्री में तीखी गिरावट दिखी है, पर साख के आंकड़ें तो विमुद्रीकरण से पहले ही कमजोर पड़ रहे थे, हां नवंबर 8 के बाद ये पहले से ही विद्यमान प्रवृत्तियां कुछ और बलवती हो गई हैं। वर्ष 2016-17 में प्रारंभ अन्य नीतियों के प्रभाव का समंजन करने के बाद अप्रत्यक्ष कर संकलन की राशियां

रेखाचित्र 14 में 'ARM' द्वारा चिन्हित टूटी रेखाओं द्वारा दिखाई गई है। ये सकल आंकड़ों से कुछ कमजोर दिखाई दे रही है, किन्तु यहां भी वृद्धि निर्विवाद है। अतः इस निष्कर्ष तक पहुंच जाना उचित ही होगा कि वास्तविक जीडीपी और आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर विमुद्रीकरण का कुछ नकारात्मक प्रभाव तो पड़ा है, किन्तु वह अस्थायी है। यहां प्रश्न उठता है, कितना और कहां तक? संक्षिप्त सा उत्तर तो यही है कि यह प्रभाव 0.25 और 0.50 प्रतिशत अंकों के बीच सीमित रहा है, जबकि आधार स्तर 7 प्रतिशत था। मध्यम अवधि में जीएसटी के क्रियान्वयन, विमुद्रीकरण की अनुशांगिक नीतियां अपनाए जाने तथा अन्य संरचनात्मक सुधारों से अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 8-10 प्रतिशत तक पहुंच सकती है। और यही भारत की आवश्यकता भी है। हमारा अगला अनुच्छेद इसी बात की विस्तार से चर्चा कर रहा है।

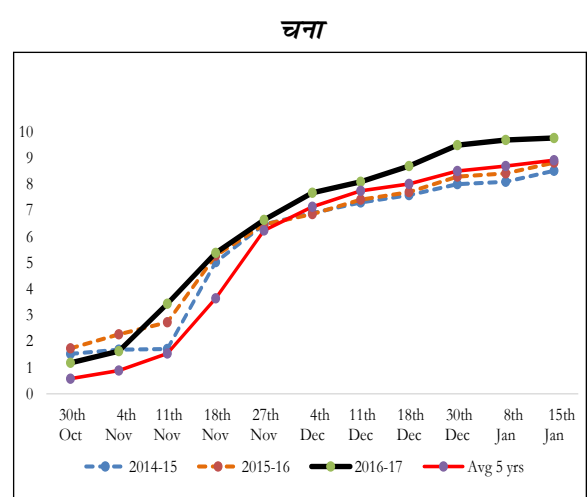
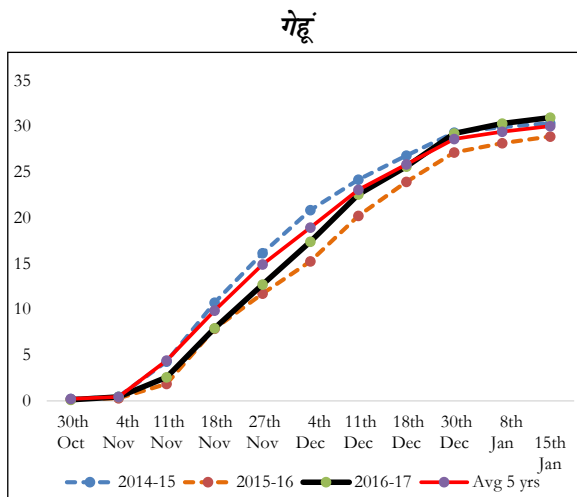
(क) रूपरेखा

3.65 अगला कदम नकदी के अभाव के आर्थिक गतिविधियों पर प्रभाव का आंकलन है। इस कार्य की मानक विधि जाने पहचाने 'मुद्रा के परिमाण सिद्धांत' वाले समीकरण का प्रयोग ही है। इस समीकरण के अनुसार: $MV=PY$, जहां

M = मुद्रा की आपूर्ति

V = परिचलन वेग, मुद्रा के परिचलन की दर, (अर्थात् अंतिम विक्रय के मान, GDP और रूपयों की संख्या का अनुपात)

रेखाचित्र 13 : रबी मौसम में गेहूं और चने की बुवाई (मिलियन हैक्टेयर में)



स्रोत : कृषि मंत्रालय

P = कीमत स्तर

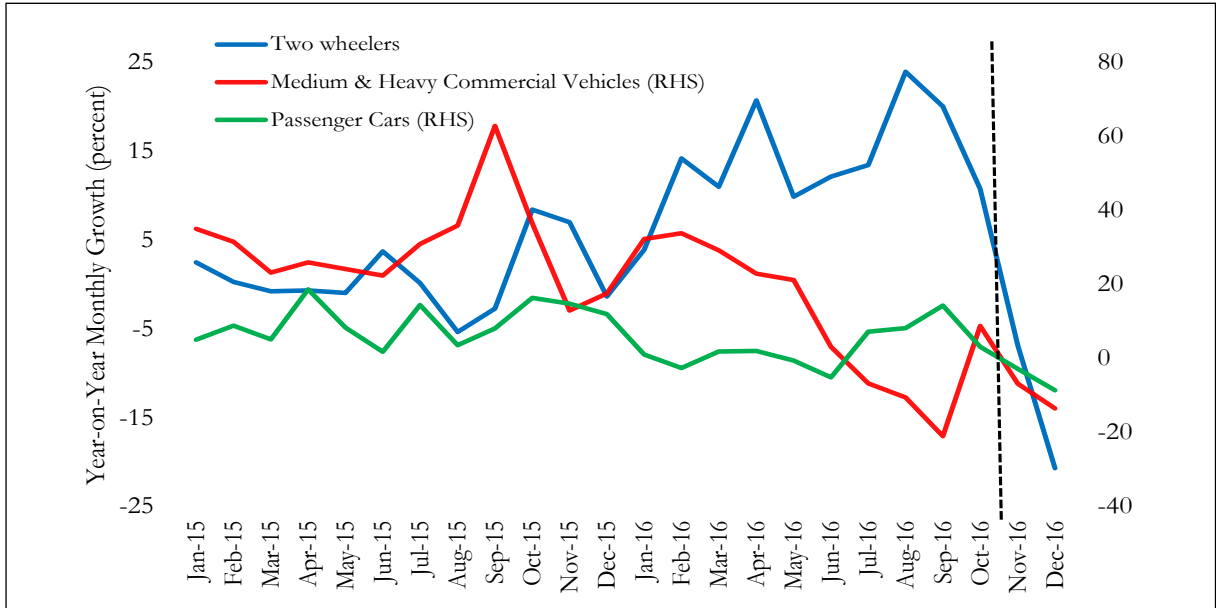
Y = वास्तविक जीडीपी

3.66 सीधे शब्दों में यह समीकरण कहता है कि यदि मुद्रा की आपूर्ति घटा दी जाए तो बची हुई मुद्रा के भंडार का अधिक गहनता से प्रयोग करना होगा अथवा

फिर मौद्रिक जीडीपी की कमी को सहना होगा। मौद्रिक जीडीपी में इस कमी का कुछ अंश कीमतों में कमी का रूप भी ले सकता है। किन्तु, वास्तविक आर्थिक गतिविधियों के स्तर पर भी कुछ प्रभाव अवश्य होगा।

(ख) प्रतिमान का व्यवहारिक प्रयोग : अर्थव्यवस्था के नकद एवं गैर नकद अनुपातों का अनुमान लगाएं

रेखाचित्र 15 : मोटर वाहनों की बिक्री, (वर्षानुगत, प्रतिशत)

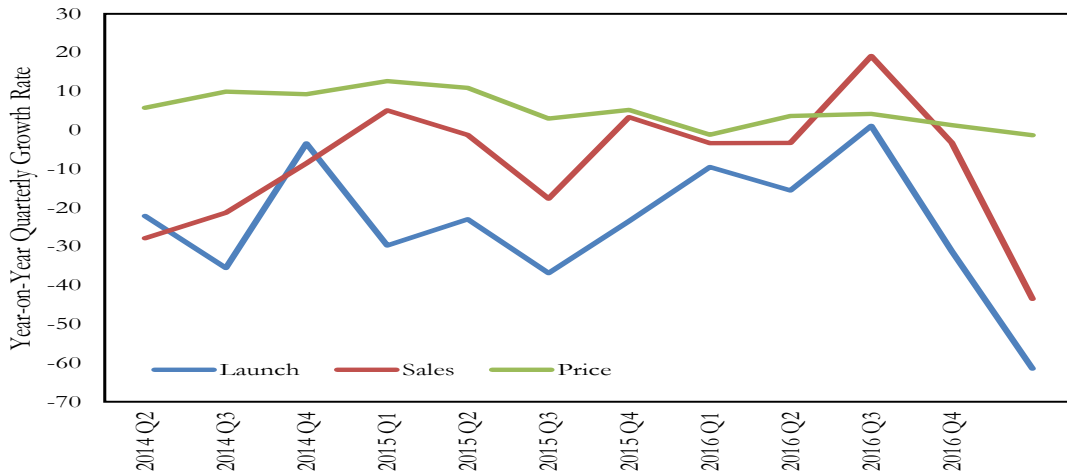


स्रोत : सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स।

स्त्रोत: राजस्व विभाग और सर्वेक्षण परिकलन

रेखाचित्र 16 : भवनसंपदा कीमतें (वर्षानुगत त्रैमासिक प्रतिशत)¹²

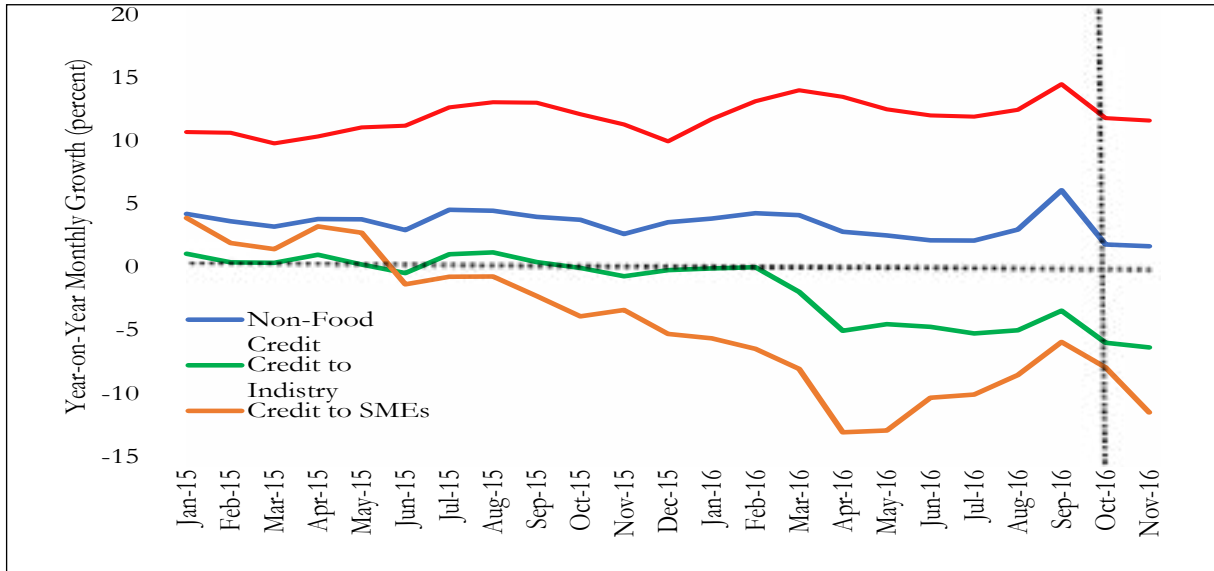
Real Estate



स्रोत : फ्रैंक नाइट आंकड़े एवं समीक्षा गणनाएं

¹² फ्रैंक नाइट द्वारा संकलित भवन संपदा आंकड़े कैलेंडर वर्षानुसार होते हैं अर्थात Q4 का अर्थ है अक्टूबर से दिसंबर की तिमाही।

रेखाचित्र 17 : वास्तविक साख संवृद्धि (वर्षानुगत प्रतिशत)



स्रोत: आरबीआई

नोट : उपभोक्ता कीमत सूचक, नई श्रृंखला, 2012 कीमतों द्वारा अपस्फायित

और यह मान्यता बना कर चले कि विमुद्रीकरण का अर्थव्यवस्था के नकदविहीन अंश पर कोई प्रभाव नहीं होगा।

3.67 इस समीकरण को व्यवहारिक स्वरूप प्रदान कर इसके आधार पर पूर्वाकलन करने से पूर्व दो संकल्पनात्मक मुद्दों का स्पष्टीकरण आवश्यक है। पहला प्रश्न तो मुद्रा की आपूर्ति की परिभाषा से जुड़ा है। सामान्यता अर्थशास्त्री आपूर्ति की व्यापक अवधारणा का प्रयोग करते हैं, उसमें नकद और बैंक जमाएँ सम्मिलित रहते हैं। जमाओं को नकदी का “निकट स्थानापन्न” माना जाता है। किन्तु नवंबर 8 के कदम का एक बड़ा आयाम तो नकद और जमा के बीच परिवर्तनीयता को बाधित करना था। नकद को बैंक में जमा करना आसान नहीं रहा तो बैंक खातों से नकद निकालने पर भी अनेक रूकावटें लगा दी गई थी। अतः नकद और बैंक जमाओं पर अलग-अलग विचार करना आवश्यक हो गया है।

3.68 इसी प्रकार औपचारिक एवं अनौपचारिक अर्थव्यवस्थाओं में भेद करना भी आवश्यक है। स्पष्टतः नकदी के अभाव का अनौपचारिक अर्थतंत्र पर प्रभाव अवश्य पड़ा होगा। यह अपने संचलन के लिए मुख्यतः

नकदी पर निर्भर क्षेत्र अर्थव्यवस्था के आधो भाग के समान माना जाता है (सेन, 2016)। यदि उपभोक्ता की अपने भुगतान में नकदी प्रयोग की प्रवृत्तियों पर ध्यान दें तो यह अर्द्धांश का अनुमान बहुत निम्न भी सिद्ध हो सकता है, फिर तो अर्थव्यवस्था में उत्पादन की नकदी की सफलभता पर निर्भरता और अधिक हो सकती है।

3.69 यह भी इतना ही स्पष्ट है कि बैंक व्यवस्था पर निर्भर रहने वाले औपचारिक आर्थिक तंत्र पर विमुद्रीकरण का कोई प्रभाव नहीं हुआ होगा। वहां तो तरलता में और वृद्धि हो गई है। अतः दोनों क्षेत्रों पर पृथक-पृथक विचार करना ही उपयुक्त होगा। यह मानकर चलना उचित है कि नकदी के अभाव का प्रभाव केवल अनौपचारिक क्षेत्रक पर पड़ा था, औपचारिक तंत्र इससे मुक्त प्रायः ही रहा।

3.70 हां यह कथन पूर्णतः सत्य नहीं होगा, क्योंकि द्वितीय चक्र के महत्वपूर्ण प्रभाव अवश्य रहते हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में मंदी के कारण अपना रोजगार खो बैठे कर्मियों ने दुपहिया वाहनों जैसे औपचारिक क्षेत्रीय उत्पादों की अपनी खरीदारी एक बार तो रोक ही दी थी।¹³ यह भी संभव है कि कुछ अनौपचारिक

¹³ मुख्य बात तो यह है कि औपचारिक एवं अनौपचारिक क्षेत्र परस्पर अच्छी तरह गुंथे होते हैं। एक की समस्या दूसरे को अवश्य प्रभावित करती है। अनेक औपचारिक क्षेत्र की फर्म अनौपचारिक क्षेत्र के आपूर्तिकर्ताओं पर ही अपना व्यवसाय चलाने के लिए निर्भर रहते हैं।

क्षेत्र व्यापारी, किराने वाले आदि विक्रय बिन्दु उपकरण लगाकर औपचारिक बैंक व्यवस्था के साथ जुड़ गए हों। साथ ही अनौपचारिक क्षेत्र में अस्थायी रूप से ही सही कुछ उधार देना भी आरंभ हो गया। नियमित ग्राहकों को किराने वाले एवं अन्य छोटे दुकानदार यह कहने लगे थे कि आप कल परसों जब सुविधा हो, भुगतान कर दीजिए।

3.71 अप्रत्यक्ष मांग और डिजिटलाइजेशन के साख के प्रभाव हमें विपरीत दिशाओं में खींचते हैं। पहला नकदी के अभाव के प्रभाव को और गहरा कर देता है तो दूसरा उसे कुछ कम कर देता है। हमने दो परिदृश्यों की कल्पना की है और उनके लिए अर्थव्यवस्था की नकद गहनता तथा उसमें नवंबर 8 से मार्च 2017 के अंत तक होने वाले परिवर्तन विषयक पृथक-पृथक मान्यताएं बनाई हैं।

3.72 यह रूपरेखा अपने आप में मौद्रिक जीडीपी संवृद्धि के अनुमानों को वास्तविक एवं कीमत घटकों में विभाजित करने के विषय में अधिक कुछ नहीं बता पाती। किन्तु यदि विमुद्रीकरण मुख्यतः एक सकल मांग पक्षीय संक्षोभ है तो हमें कीमतों में कुछ कमी की अपेक्षा अवश्य होनी चाहिए। अतः हम कीमतों का मार्च, 2017 के अंत तक प्रेक्षण/पूर्वाकलन दोनों परिदृश्यों के अनुसार कर रहे हैं। एक वह जहां विमुद्रीकरण स्फीति को घटाएगा तथा दूसरा जहां स्फीति अप्रभावित रहेगी।

3.73 उपर्युक्त सभी चर्चाओं तथा अनिश्चतता के कारण हम एक स्पष्ट अनुमान नहीं दे पाते, हम ऐसी दो सीमाएं बताते हैं जिनके बीच कहीं वास्तविक अनुमान रहना चाहिए। मौद्रिक जीडीपी पर प्रभाव संवृद्धि दर में गिरावट के रूप में होगा। यह गिरावट 0.25 से 0.50 प्रतिशत अंक की हो सकती है (आधार अनुमान 7 प्रतिशत)। मध्यम अवधि में जीएसटी लागू होने, विमुद्रीकरण के अन्य अनुषांगिक कार्य संपादित होने और अन्य संरचनात्मक सुधार हो जाने के बाद अर्थव्यवस्था की संवृद्धि दर 8-10 प्रतिशत की सीमाओं में पहुँच जाएगी। इसी की भारत को जरूरत भी है। इन अनुमानों की व्याख्या कैसे करे और कैसे नहीं करें, ये बातें हम बॉक्स-2 में स्पष्ट कर रहे हैं।

3.74 अन्त में एक और महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दें : जीडीपी संवृद्धि पर विमुद्रीकरण का दुष्प्रभाव बहुत ही अस्थायी होगा। एक बार नकदी की आपूर्ति पुनः पूर्ववत् स्तर तक पहुँचने (यह भी मार्च 2017 के अन्त तक हो जाने की आशा है) पर अर्थव्यवस्था पुनः अपनी पुरानी रफ्तार पर पहुँच जाएगी। संभव है पुनः उछलकर अपने पुराने औसत को प्राप्त करने की ललक भी दिखाई दे जाए। अतः 2017-18 में वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर के $6\frac{3}{4}$ - $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत की सीमाओं में रहने का पूर्वानुमान बन रहा है।

3.75 अब बारी है विमुद्रीकरण के आर्थिक गतिविधियों पर प्रभावों के विषय में कुछ निष्कर्षात्मक टिप्पणियों की। यह तो स्पष्ट है कि वित्त वर्ष 2017 के उत्तरार्द्ध में दर्ज होने वाली जीडीपी संवृद्धि इन प्रभावों का न्यूनांकन ही करेगी। कारण यही है कि या तो सबसे अधिक प्रभावित अनौपचारिक क्षेत्र की जानकारी राष्ट्रीय आय लेखे में परिलिखित ही नहीं होती या फिर उसके लिए भी औपचारिक क्षेत्र के निष्पादन सूचकों के आधार पर ही कुछ अनुमानित आंकड़े जोड़ लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए अनौपचारिक क्षेत्र के उत्पादन का अनुमान भी मुख्यतः औपचारिक क्षेत्र के बड़े निकायों की जानकारी के आधार पर आंकलित औद्योगिक उत्पादन सूचक के अनुसार कर लिया जाता है। अतः उत्पादन, अर्थात् आर्थिक गतिविधियों के आपूर्ति पक्ष पर प्रभाव का निश्चित रूप से न्यूनांकन होगा। हां, जहां तक अनौपचारिक क्षेत्र की निम्न आय के औपचारिक क्षेत्र के उत्पादन की मांग पर दुष्प्रभाव हो पाते हैं, उस सीमा तक यह प्रभाव अवश्य विश्लेषण में कुछ स्थान पा जाएगा। दुपहियां वाहनों की मांग में गिरावट इसी की ओर इंगित कर सकती है।

3.76 कुल मिलाकर, विमुद्रीकरण नकदी और मुद्रा के अन्य स्वरूपों के बीच प्रतिस्थापनीयता का एक अच्छा स्वभाविक प्रयोग अवश्य रहेगा। विमुद्रीकरण ने इन दोनों के बीच, आपूर्ति पक्ष पर एक बहुत बड़ी खाई पैदा कर दी है। यदि ये दोनों स्वरूप परस्पर प्रतिस्थापकीय हैं तो प्रभाव अपेक्षाकृत सीमित रहेगा। दूसरी ओर यदि नकद का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता, तो यह प्रभाव बहुत बड़ा हो जाएगा।

(ग) सत्यापन का प्रयास : नकदी और मांग जमाएं संपूर्ण रूप से प्रतिस्थापक हैं बनाम नकदी एक बाध्यताकारी संरोध है।

3.77 यहां वर्ष के उत्तरार्द्ध के लिए संवृद्धि अनुमानों पर केंद्रित एक सत्यापन प्रयास किया गया है।¹⁴ मुद्रा (नकद तथा मांग जमाएं) और नकदी के लिए निहित परिचलन वेग का आंकलन कर यह देखा गया है कि ऐतिहासिक अनुभवों की तुलना में इस अवधि में इनका व्यवहार कैसा रहा है। यह प्रयोग भी दो परिदृश्यों के लिए अलग-अलग किया गया है। पहले में मुद्रा का वेग आंकलित किया गया है (रेखाचित्र-18) यहां नकद और मांग जमाओं को संपूर्ण प्रतिस्थापक माना गया है। अतः नकदी में कमी का कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अन्य प्रकार की मुद्रा (बैंक जमाओं) में तो वृद्धि हो ही गई थी। यह एक पराकाष्ठ मान्यता है। प्रत्येक परिदृश्य के लिए निहित वेग का मान ऐतिहासिक प्रवृत्ति आधारित मान से कुछ अधिक ही पाया गया है।

3.78 दूसरा परिदृश्य (रेखाचित्र-19) में केवल नकदी

का निहित वेग मापा गया है। यहां मान्यता है कि नोटबंदी की अवधि में नकदी की सफलभता सभी लेनदेनों में एक प्रभावी संरोध बन गई थी। अतः इस मान्यता के अधीन तो मापित निहित वेग ऐतिहासिक प्रवृत्ति से बहुत ही भिन्न होना चाहिए था।

3.79 किन्तु वास्तविकता तो कहीं इन दोनों पराकाष्ठापूर्ण मान्यताओं के आधार पर किए गए आंकलन के बीच में कहीं होगी। अतः इन अनुमानों के व्यवहार्य होने की संभाव्यता विमुद्रीकरण अवधि में नकद और गैर नकद (जमाओं) के बीच प्रतिस्थापनीयता पर निर्भर रहेगी। यह प्रतिस्थापनीयता जितनी अधिक होगी, संवृद्धि अनुमान उतने ही अधिक संभाव्य होंगे और प्रतिस्थापनीयता जितनी कम होगी जीडीपी पर उतना ही अधिक गंभीर नकारात्मक प्रभाव होगा।

(घ) आपूर्ति पक्षीय प्रभाव

3.80 ये अनुमान पूरी तरह से विमुद्रीकरण के तरलता पर प्रभाव पर आधारित हैं, इनमें धनसंपदा, सकल आपूर्ति

बॉक्स-2 : जीडीपी विमुद्रीकरण प्रभाव : संभावित अपव्याख्याओं का पूर्व स्पष्टीकरण

CSO और समीक्षा द्वारा जीडीपी संवृद्धि, विशेषकर विमुद्रीकरण के प्रभावों विषयक अनुमानों की कई प्रकार अपव्याख्याएं संभव है। इसीलिए इस प्रकार की आशंकाओं का “पूर्व अनुमान” लगाकर उनके विषय में स्पष्टीकरण करना अनिवार्य हो जाता है।

उदाहरण के लिए, कुछ टीकाकारों को इस वर्ष की वास्तविक जीडीपी संवृद्धि दर की पिछले वर्ष की दर (7.6 प्रतिशत) से तुलना करने कल ललक होगी। किन्तु ऐसा करना उपयुक्त नहीं होगा। इस वर्ष के निष्पादन पर विमुद्रीकरण के अतिरिक्त और भी अनेक कारकों के प्रभाव रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों की गिरावट बंद हो चुकी है। अब अर्थव्यवस्था को उस गिरावट का सहारा नहीं मिल पा रहा। अतः विमुद्रीकरण के बिना भी जीडीपी संवृद्धि दर पिछले वर्ष से कुछ भिन्न अवश्य रहती।

अतः तुलना का एक बेहतर आधार उस संवृद्धि दर से मिल सकता है, जो विमुद्रीकरण नहीं होने की अवस्था में हमारी जीडीपी प्राप्त कर जाती। यहां CSO द्वारा तैयार जीडीपी संवृद्धि का अग्रिम अनुमान (7.1 प्रतिशत) काम आ सकता है। यह समीक्षा के अपने अग्रिम अनुमान के निकट भी है।

इनसे भी कहीं बेहतर तो वास्तविक नहीं मौद्रिक जीडीपी संवृद्धि की तुलना होगी। आखिर विमुद्रीकरण एक मौद्रिक मांग पक्षीय संक्षोभ ही तो है। अतः इसके प्रभाव भी सबसे पहले मौद्रिक रूप से ही होने चाहिए। यही नहीं, जैसा कि 2015 के वर्ष मध्य आर्थिक विश्लेषण में स्पष्ट किया गया था, CPI तथा WPI के बीच पैदा हो गई विस्तृत खाई ने जीडीपी अपस्फायक का मापन ही कठिन बना दिया है। उसी अपस्फायक द्वारा हम मौद्रिक जीडीपी के आंकड़ों को वास्तविक जीडीपी में परिवर्तित करते रहे हैं। यह खाई अब शून्य के निकट पहुँच रही है। दिसंबर 2016 के आंकड़े यही बता रहे हैं, फिर भी विमुद्रीकरण के प्रभावों की एक बेहतर झलक मौद्रिक आंकड़ों में ही मिल पाएगी।

अतः विमुद्रीकरण के प्रभावों का सबसे सटीक आंकलन वास्तविक मौद्रिक जीडीपी संवृद्धि की तुलना समीक्षा द्वारा तैयार पूर्वानुमानों से करने पर हो पाएगा (वह पूर्वानुमान विमुद्रीकरण के बिना मौद्रिक जीडीपी की संवृद्धि को ही दर्शा रहा था)। CSO के अनुसार यह तुलनीय आंकड़ा 11.9 प्रतिशत था तो समीक्षा के अनुसार 11 प्रतिशत था।

अंत में, कुछ टीकाकारों को समीक्षा के वास्तविक जीडीपी संवृद्धि के अनुमानों की अन्य संस्थानों, विशेषकर विश्व बैंक, IMF आदि के अनुमानों से तुलना की ललक भी होगी। किन्तु उन संस्थानों ने 2016-17 का जो (विमुद्रीकरण पूर्व) पूर्वानुमान लगाया था वह CSO तथा समीक्षा के अग्रिम अनुमानों से कहीं उच्चतर था। अतः अधिक उपयुक्त तुलना तो पूर्वानुमानों के स्तरों की नहीं बल्कि उन पूर्वानुमानों में परिवर्तन की होनी चाहिए।

¹⁴ एक अन्य संभावना इसी प्रयास का पूरे वर्ष के लिए करने की थी। किन्तु विमुद्रीकरण तो केवल उत्तरार्द्ध को प्रभावित करेगा और वैसे भी जुलाई-सितंबर की तिमाही में मौद्रिक मानों में असामान्य उतार-चढ़ाव दिखाई दिए थे। इसीलिए यह विश्लेषण नवंबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि तक ही सीमित रखा गया है।

या अनिश्चितता का कोई योगदान नहीं है। यह अन्य प्रभाव तो परिमाणात्मक स्वरूप में पूर्वाकलित नहीं हो सकते, हां इनका कुछ गुणात्मक आंकलन अवश्य संभव होता है। संभव है कि वित्त वर्ष की तृतीय तिमाही में अनिश्चितता के कारण कुछ उपभोक्ताओं और फर्मों ने अपने क्रय संबंधी तथा निवेश निर्णय स्थगित कर दिए हों। किन्तु जैसे-जैसे अर्थव्यवस्था का पुनःमुद्रीकरण होगा, परिस्थितियां सामान्य होगी, अनिश्चितता का निवारण हो जाएगा और वित्त वर्ष के अंत तक मांग को पुनः अपने पूर्ववर्ती स्तरों की ओर लौट आना चाहिए। इसी प्रकार, प्रारंभिक महीनों में एक संपदा संक्षोभ था, नकद संसाधन बैंकों में जमा करने पड़ गए थे (और वहां से उन्हें निकालना आसान नहीं था)। किन्तु जैसे-जैसे आहरण पर रोक में छूट मिली, इस प्रभाव का भी निवारण हो जाना चाहिए। हां, जिस सीमा तक उक्त धन का कुछ हिस्सा (सरकार सहित) अधिक व्यय प्रवृत्ति वाले वर्गों को अन्तरित हुआ होगा, उस सीमा तक मांग में अंततः वृद्धि ही होगी।

3.81 यह अपेक्षाकृत लाभप्रद परिणाम तभी संभव होगा जब पुनःमुद्रीकरण तेजी से हो जाए (रेखाचित्र 11ख में दर्शाया था कि वित्तवर्ष के अन्त तक 90 प्रतिशत तक, मुद्रा की विनिमय मांग अवश्य पूरी होने लगेगी), निर्णायक

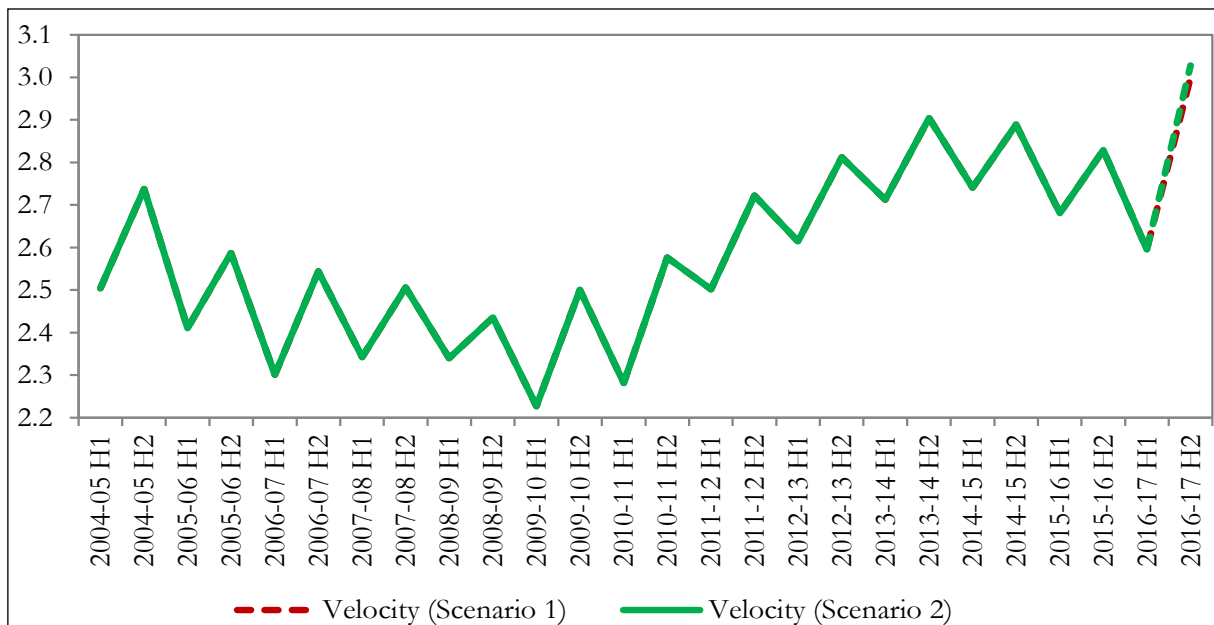
नीतियां अपनाकर अनिश्चितता का निवारण किया जाए तथा अति उत्साही कर प्रशासकों पर अंकुश रखा जाए। तभी विमुद्रीकरण के प्रभावों का स्वरूप गैर-स्थायी बन पाएगा।

3.82 विमुद्रीकरण कुछ कृषि उत्पादों की आपूर्ति को भी प्रभावित कर सकता है। यहां दूध का संग्रह कम हुआ है, दक्षिण प्रांतों की अनावृष्टि का प्रभाव चीनी की आपूर्ति पर अवश्य होगा और आलू तथा प्याज की बुवाई-रोपाई भी कम हुई है। अतः अभाव और कीमत वृद्धि के पटल पर 2015-16 में जो हालत दालों के कारण हुई थी, अन्य पदार्थों के कारण वैसी स्थिति से 2017-18 में बचने के लिए सतर्कता आवश्यक होगी।

VIII. सरकार के पक्ष में पुनः वितरण

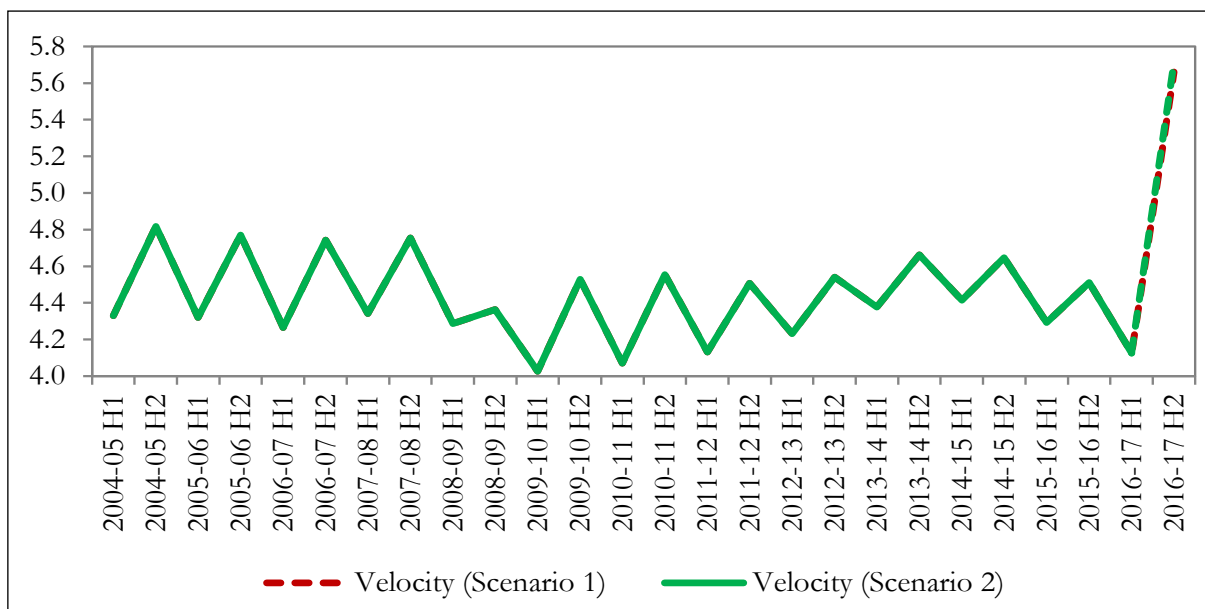
3.83 विमुद्रीकरण संसाधनों का पुनः वितरण भी करेगा। जहां तक कालेधन के स्वामी किसी अन्य को कतार में खड़े होकर अपना धन सफेद करने में सफल रहे हैं, उन्होंने भी कतार में लगने वालों को कुछ न कुछ 'कमीशन' दिया है। इस प्रकार उस धन का निम्न व्यय प्रवृत्ति से उच्च व्यय प्रवृत्ति वर्ग को आंशिक अन्तरण तो हो ही गया है। किन्तु सबसे बड़ा पुनःवितरण प्रभाव तो निजी क्षेत्र से सरकार को अन्तरण होगा। उससे आगे

रेखाचित्र 18 : नकद एवं गैर नकद मुद्रा का अर्द्धवार्षिक परिचलन वेग (गैर नकद एवं नकद)



स्रोत : समीक्षा गणनाएं

रेखाचित्र 19 : अर्द्धवार्षिक मुद्रा का परिचलन वेग (केवल नकद)



स्रोत : समीक्षा गणनाएं

सारी अर्थव्यवस्था पर होने वाला प्रभाव इस बात पर निर्भर करेगा कि सरकार उस अन्तरित धनराशि का क्या प्रयोग करती है।

3.84 विमुद्रीकरण का राजकोष के खातों पर प्रभाव इस प्रकार रहेगा :

3.85 धन संपदा का लाभ : रिजर्व बैंक / सरकार को उस नकद राशि के समान धन लाभ होगा जो बैंक व्यवस्था को लौटाई नहीं जाएगी।

3.86 अल्पकालिक प्रवाह प्रभाव : निवल रूप में इस प्रभाव का आंकलन कठिन है, क्योंकि कई प्रकार के अन्तर्प्रवाह भी चल रहे हैं। कालेधन के बैंक खातों में जमा होने पर उस पर उगाहा गया आयकर (खंड IV में चर्चित) कुल कर संकलन में वृद्धि करेगा। राज्य सरकारों को बकाया कर राशियों के भुगतान के समाचार भी आ रहे हैं, साथ ही विद्युत वितरकों को भी भुगतान में उछाल आया है। इसके प्रति तीन नकारात्मक प्रभाव भी हैं :

- सामान्य रूप से पुराने (घिसेपिटे/गंदे हो गए) नोटों के स्थान पर नए नोट छापने से कहीं अधिक भारी परिमाण में छपाई की लागत,

- बैंक व्यवस्था में तरलता के उफान को नियंत्रित रखने हेतु बाजार स्थिरीकरण योजना बांड जारी करने की विवशता,
- मौद्रिक जीडीपी में कमी आने पर निगम एवं अप्रत्यक्ष कर राजस्व में कमी की आशंका होगी, किन्तु अभी तक इस कमी का कोई संकेत नहीं मिला है।

3.87 इस सारे कार्य की सकल लागत तो एक वर्ष पूरा होने के पश्चात ही पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी।

IX. सफलता के कुछ चिन्ह

3.88 विमुद्रीकरण के दीर्घकालिक लाभ संभव हैं। ये अगले 6 महीनों में तो नहीं दिखाई देने वाले, किन्तु एक वर्ष बीतते-बीतते इनका क्षितिज दर्शन अवश्य प्रारंभ हो जाएगा। और, सफलता के इन चिन्हों की पहचान इतनी कठिन भी नहीं है।

3.89 पहला चिन्ह तो डिजिटल तंत्र से जुड़े तीनों स्तरों के जनसमुदाय द्वारा डिजिटल भुगतान को अपनाया जाना है। हमने ये तीन वर्ग क्रमशः स्मार्टफोन प्रयोक्ता, सामान्य मोबाईल फोन प्रयोक्ता और फोनविहीन के रूप में बनाए हैं। इस पटल पर प्रारंभिक चिन्ह उत्साहवर्धक हैं।

3.90 दूसरे, नकद जीडीपी अनुपात में कमी आनी चाहिए, क्योंकि अपेक्षाकृत अधिक बचतें औपचारिक वित्त व्यवस्था में प्रवाहित होने लगेंगी तथा कालेधन में कमी आएगी। कालेधन के एक अनुमान के आधार पर तो कहा जा सकता है कि नकद जीडीपी अनुपात में 2 प्रतिशत अंकों की स्थायी कमी आ जाएगी।

3.91 संभवतः कर राजस्व संग्रह तो सफलता का सर्वश्रेष्ठ चिन्ह होगा। नए करदाताओं की संख्या तथा सकल घोषित आय में आंकड़ों में समय के साथ-साथ वृद्धि होगी। वर्ष 2013-14 की अवस्था हम तालिका-3 में प्रस्तुत कर रहे हैं। समय के साथ-साथ यहां दर्शाई गई सभी संख्याओं में महत्वपूर्ण वृद्धि होनी चाहिए। यही सफलता का सबसे प्रामाणिक चिन्ह होगा।

3.92 विमुद्रीकरण ने किसी सीमा तक अप्रत्यक्ष कर अनुपालन नहीं करने की लागतें बढ़ा दी हैं। अतः सेवाकर, उत्पादन शुल्क तथा राज्यों के मूल्य वृद्धि करदाताओं की पंजीकृत संख्याओं में भी वृद्धि की आशा है। ये संख्याएं भविष्य में निरंतर वृद्धिशील होनी चाहिए।

तालिका 3 : वैयक्तिक आयकर दाताओं का विवरण : वित्तवर्ष 2013-14

सकल आय सीमाएं	करदाता संख्या (लाखों में)	सकल आय (लाख करोड़ रूपए)
रु. 0-2.5 लाख	137.2	2.6
रु. 2.50-5.0 लाख	138.5	4.8
रु. 5.00-10.00 लाख	65.1	4.4
रु. 10.00 लाख और अधिक	24.4	6.7
विवरणियां भरने वाले करदाता	365.1	18.6
विवरणियां नहीं भरने वाले करदाता	172.9	
सकल योगफल	538.0	

X. दीर्घकालिक लाभों को अधिकतम एवं अल्पकालिक लागतों को न्यूनतम करना

3.93 अब आगे चलते हुए विमुद्रीकरण की लागतों को न्यूनतम और इसके लाभों को अधिकतम करने पर आग्रह होना चाहिए।

3.94 लागत कम करने के पक्ष पर यथाशीघ्र नकदी के अभाव को दूर करने पर बल दिया जाना चाहिए। जितनी शीघ्र पुनःमुद्रीकरण हो जाएगा, विमुद्रीकरण के प्रभाव उतने ही अल्पकालिक या अस्थायी तथा कम गंभीर होंगे।

3.95 एक अन्य बात पर बल देना आवश्यक है : करेन्सी की आपूर्ति वास्तविक मांग के अनुरूप होनी चाहिए, सरकारी तौर पर निर्धारित “वांछनीय मांग के अनुसार नहीं”। दूसरे शब्दों में, रिजर्व बैंक को आन्तरिक प्रतिस्थापनीयता को पुनः स्थापना कर जन सामान्य को उसकी आवश्यकता के अनुसार नकदी सफलभ करानी चाहिए। खातों से आहरण सीमाओं को शीघ्र समाप्त करने पर जनता का विश्वास पुनः जागृत होगा, इसी प्रकार नकद आहरण पर कोई जुर्माने नहीं लगने चाहिए, अन्यथा लोग फिर से नकद राशियां अपने पास ही दबा कर रखने लगेंगे।

3.96 आन्तरिक परिवर्तनीयता प्रत्येक वित्तीय व्यवस्था का आधार होती है। इसके अनेक अत्यंत ही व्यवहारिक कारण हैं। जब तक जन सामान्य को यह भरोसा नहीं होगा कि बैंक में जमा राशियां बिना बाधा के नकद में बदली जा सकती हैं, वे अपनी कमाई की रकम को बैंक में जमा करने/रखने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। वे उस रकम को अपने पास दबाकर रखेंगे, इस प्रकार न तो औपचारिक वित्त व्यवस्था को संसाधन मिल पाएंगे और न ही अनौपचारिक अर्थतंत्र के संचालन के लिए नकदी। इसका सबसे बड़ा प्रभाव समाज के गरीब वर्ग पर ही पड़ेगा, इस बात की बहुत संभावना है कि वही अनौपचारिक तंत्र में काम कर रहे हो और वैसे भी प्रायः धनिक वर्ग को नकदी के दर्शन पहले होते हैं और वही उसे दबाकर बैठ जाएंगे। धीरे-धीरे कम मूल्य के नोटों में वृद्धि होनी चाहिए (उच्च मूल्य के नोटों की तुलना में)। किन्तु सकल मुद्रा की आपूर्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होने चाहिए।

3.97 साथ ही, इस बीच नहीं लौटाए गए नोटों के रूप में सरकार को होनेवाली अनायास प्राप्तियों का प्रयोग चालू खाते पर उपभोग के लिए नहीं बल्कि पूंजी व्यय के लिए होना चाहिए। यह अनायास प्राप्ति केवल एक बारगी प्राप्ति है, अतः इसका प्रयोग भी एक बारगी कार्यों के निमित्त होना चाहिए। इस प्रयोग से व्यय को स्थायी रूप से बढ़ाने वाली अधिकारिताओं का सृजन नहीं होना चाहिए।

3.98 मध्यमकालिक दृष्टि से डिजिटलाइजेशन को मिला प्रोत्साहन चलते रहना चाहिए। इस प्रयास को आगे बढ़ाने हेतु कुछ नियम/सिद्धांत बन जाने चाहिए। न तो डिजिटलाइजेशन कोई रामबाण औषधि है और न ही नकद इतना बुरा है। सार्वजनिक नीति को भुगतान की दोनों विधियों की लागतों और लाभों के बीच संतुलन बनाना चाहिए। दूसरे, डिजिटलाइजेशन की और समाज को धीरे-धीरे अग्रसर करना चाहिए, इस प्रयास में अभी तक डिजिटल प्रौद्योगिकी से वंचित वर्ग का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। अर्थात् जनता के चयन का सम्मान करना चाहिए, उसपर हुकम नहीं चलाना चाहिए और नीति को समाहनकारी स्वरूप मिलना चाहिए, नियंत्रणकारी नहीं।

3.99 जहां तक डिजिटलाइजेशन के लिए प्रोत्साहन की बात है और नकदी को प्राप्त प्रोत्साहन निरस्त करने की बात है, तो इस प्रकल्प की लागतें सरकार/सरकारी क्षेत्र तथा रिजर्व बैंक को वहन करनी चाहिए। इनका भार उपभोक्ता एवं वित्तीय लेनदेन सहज बनाने वाली संस्थाओं पर नहीं पड़ना चाहिए। यह प्रोत्साहन प्रकल्प सावधिक होना चाहिए, क्योंकि इस डिजिटलाइजेशन में वृद्धि होने पर एक स्तर से आगे तो इसे निजी रूप से भी लाभप्रद हो जाना चाहिए। इस प्रकार की भुगतान व्यवस्था में विश्वास दृढ़ बनाने के लिए साइबर सुरक्षा व्यवस्था को बहुत सशक्त बनाना आवश्यक है। एक अन्य महत्वपूर्ण आवश्यकता है कि भुगतान प्रक्रिया विभिन्न तंत्रों के बीच सुचारू रूप से चलती रहे। यही बात डिजिटलाइजेशन की ओर आगे प्रगति के लिए अभी नवसृजित UPI को और व्यापक एवं विकसित करने का आग्रह कर रही है।

3.100 **सबसे बड़ी बात तो यह है** : यदि यह सुनिश्चित करना है कि विमुद्रीकरण सचमुच में व्यवहार में दीर्घकालिक बदलाव का उत्प्रेरक सिद्ध हो तो हमें

इसका साथ देनेवाले ऐसे गैर-दण्डात्मक एवं प्रोत्साहन मित्र कदम भी उठाने होंगे जो कर वंचना के लिए वर्तमान प्रोत्साहनों को कम कर दें। विमुद्रीकरण निश्चित रूप से एक सशक्त छड़ी रहा है। अब इसका साथ देने के लिए कुछ चारे (गाजरो) की भी जरूरत है। यहां एक पंचमुखी युक्ति अपनाई जा सकती है।

- एक ऐसी जीएसटी प्रणाली लागू की जाए जो भूमी एवं अचल संपत्ति के लेनदेन सहित सभी कालेधन का सृजन करने वाले कार्यों को अपने वितान में समेट लें;
- वैयक्तिक आयकर और स्टैप शुल्क दरें कम की जा सकती हैं;
- धीरे-धीरे आयकर जाल को फैलाया जा सकता है, यह संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुरूप हो और इसमें सभी उच्च आमदनियों को समाहित कर लिया जाए (आखिर कालाधन इस प्रकार का सूक्ष्म क्षेत्रीय भेदभाव कहां करता है?);
- निगम कर में कमी की काल सारिणी को अधिक त्वरण दिया जा सकता है; और
- कर प्रशासन को सुधार उसमें मनमानापन घटाया जा सकता है तथा साथ ही उसमें उत्तरदायित्व (जवाबदेही) में सुधार लाया जा सकता है।

3.101 अन्त में, यह भी आवश्यक है कि नई घोषित (अभी तक छुपाई गई) संपदा को लेकर प्रत्येक स्तर के कर प्रशासक उन संपदाधिकारियों का उत्पीड़न प्रारंभ नहीं कर पाएं। जानकारी के बेहतर प्रयोग, साक्ष्य के आधार पर संवीक्षा और अंकेक्षण तथा कर आंकलन अनुपालन को यथासंभव ऑनलाईन बना कर प्रशासकों एवं करदाताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर भेंट की संभावनाएं न्यूनतम की जानी चाहिए। अब वह समय आ रहा है जब जीएसटी प्रत्येक लेनदेन को लेकर बहुत अधिक आंकड़ों (जानकारी) का सृजन करेगा। अतः केन्द्र में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर प्रशासकों के बीच जानकारी के आदान-प्रदान, वह भी राज्य सरकारों के साथ समन्वयपूर्वक, में वृद्धि होनी चाहिए। इससे न केवल अप्रत्यक्ष करों का बल्कि प्रत्यक्ष करों का भी गैर दण्डात्मक विधियों से बेहतर अनुपालन संभव हो

पाएगा। कर प्रशासन को विशाल आंकड़ा समुच्च्य और डिजिटल युग द्वारा सफल बनाए जा रहे सुअवसरों को अंगीकार करना चाहिए।

संदर्भ

1. Acharya, Shankar N. (1986), "Aspects of the black economy in India", National Institute of Public Finance and Policy
2. Government of India (2016), "Committee on Digital Payments", Ministry of Finance
3. Henry, James S. (1980), "The Cash Connection: How to Make the Mob Miserable", The Washington Monthly.
4. PricewaterhouseCoopers India (2015), "Disrupting cash: Accelerating electronic payments in India"
5. Rai, Suyash (2016), "A flawed policy: The real problem with demonetisation is not just in implementation", scroll.in
6. Rogoff, Kenneth S. (2016), *The Curse of Cash*, Princeton University Press
7. Sands, Peter (2016), "Making it Harder for the Bad Guys: The Case for Eliminating High Denomination Notes", Harvard Kennedy School M-RCBG Associate Working Paper No. 52
8. Sen, Pronab (2016), "Demonetisation is a hollow move", Op-ed: Mint
9. Summers, Larry (Feb 16, 2016), "It's time to kill the \$100 bill", Op-ed: Washington Post

परिशिष्ट 1. विभिन्न देशों से विमुद्रीकरण के उद्धारण

वर्ष 1982 के बाद से अचानक विमुद्रीकरण/करेंसी में भारी संकुचन की घटनाएँ¹⁵

देश	वर्ष	उठाए गए कदम	तर्काधार	प्रभाव
घाना	1982	50 सेडी नोटों का विमुद्रीकरण, देर तक कोई नोट बदली नहीं, बैंक जमाओं को निष्क्रिय किया गया।	अत्यधिक तरलता और स्फीति	बैंक व्यवस्था में विश्वास समाप्त हो गया।
म्यांमार	1985	50 और 100 क्याट के नोट बंद, सीमित नोट बदली की अनुमति, 75 क्याट के नोट प्रारंभ	कालाबाजारी का सामना करने की आवश्यकता	सार्वजनिक विरोध
	1987	25, 35 और 75 क्याट के नोट अमान्य, बदली की सुविधा नहीं नए मूल्यों के नोट जारी		चीजें खरीदकर रखने की जल्दबाजी ने स्फीति को और गंभीर कर दिया।
ब्राजील	1990	कॉलर योजना : एक सीमा से अधिक की सभी जमाएं पूरी तरह बंद कर मौद्रिक संकुचन, अर्थव्यवस्था में सूचक बंधन समाप्त, कीमती और मजदूरी पूरी तरह नियत। एक सीमा तक के पुरानी करेंसी के जमा समान दर पर नई करेंसी में बदले गए।	अतिस्फीति का सामना	उत्पादन का संकुचन, अनियंत्रित स्तर पर तरलता के पुनः संचार के कारण कीमती में धीमी कमी
	1993	रियल योजना : नई करेंसी प्रारंभ, इसकी एक इकाई पुरानी की 1000 के समान घोषित, दोनों करेंसियां साथ-साथ चलती रहीं।	अतिस्फीति का सामना	धीरे-धीरे अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ गई।
सोवियत संघ	1991	जनवरी माह में अचानक 50 और 100 रूबल के नोट वापस, नए नोटों से बदली, किन्तु केवल तीन दिन तक, वह भी प्रतिव्यक्ति बहुत कम मात्रा में।	संगठित अपराध तंत्र का सामना और अत्यधिक मौद्रिक प्रसार से मुक्ति	जनता का विश्वास भंग, अतिस्फीति प्रारंभ, नकदी समाप्त प्रायः रोजगार में भारी हानि।
रूस	1993	1991 वाले कदम जैसा ही रूस ने अपने पड़ोसियों से रूबल प्रयोग करने वाले क्षेत्र की स्थापना पर बातचीत की, किन्तु बेलारूस ही सहमत हुआ।	पुराने बैंक नोटों का परिवर्तन करने और स्फीति पर नियंत्रण की आवश्यकता	रूबल को तो बल नहीं मिला। पड़ोसी देशों की करेंसिया भी समस्याग्रस्त हुईं।
इराक	1993	25 दिनार के नोटों को देश में ही छपे निम्न गुणवत्ता नोटों से बदल दिया गया, बदली के लिए सीमित समय दिया गया, देश के उत्तरी भाग में बदली भी नहीं हुई, पुराने दिनार को ही नया दिनार मान लिया गया।	दक्षिण ईराक संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों का सामना करने के लिए देश में ही नोट छपवाने लगा, यह छपाई बजट का घाटा पूरा करने के लिए ज्यादा ही तेजी से होने लगी।	अनियंत्रित नोट छपाई का स्वभाविक परिणाम रहा स्फीति में भारी वृद्धि।
उत्तरी कोरिया	2009	पुराने नोट रद्द, पुनः मूल्यित, बदली पर कड़े नियंत्रण, जिसमें आगे कुछ छूट दी गई, फरवरी 2010 में मुक्त बाजार पर लगाई गई कुछ बाधाएं कम कर दी गईं।	काले करेंसी बाजार और स्फीति पर नियंत्रण	एक सप्ताह तक कार्यवाही रोक दी गई, करेंसी वॉन का काले बाजार में अवमूल्यन जनता का कड़ा विरोध
साइप्रस	2013	यूरो IMF के सहायता कार्यक्रम को स्वीकार करने के बाद साइप्रस ने बीमा रहित बैंक जमाओं पर एक बारगी कर लगा दिया गया।	ग्रीस द्वारा ऋण नहीं चुकाने पर बैंक प्रणाली को क्षति पहुँची, राजकोषीय एवं बैंकिंग संकट हुआ	बैंक व्यवस्था धीरे-धीरे फिर अपने पैरों पर खड़ी हो गयी।

¹⁵ अचानक विमुद्रीकरण की और भी अनेक घटनाओं की चर्चा को.एन वांचू समिति की रिपोर्ट में की गई है। इनमें बेल्लिजियम, नीदरलैंड, ग्रीस, फ्रांस, रोमानिया और श्रीलंका सम्मिलित थे।

ग्रीस	2015	जून 2015, बैंकों को कुछ समय तक बंद कर दिया गया, और पूंजी पर नियंत्रण लगाए गए।	राजकोषीय और बैंक क्षेत्र में संकट	बैंक तो जुलाई 2015 में फिर से काम करने लगे पर पूंजी नियंत्रण बने रहे।
वेनुजुएला	2016	दिसंबर 2016 में 100 बोलिवर का नोट वापिस ले लिया गया।	स्फीति और मुनाफाखोरी पर नियंत्रण के लिए	जन असंतोष

पहले से ही घोषणा कर धीमे-धीमे विमुद्रीकरण/करेंसी में तीखी कमी

देश	वर्ष	उपाय	औचित्य	प्रभाव
सिंगापुर	1967	जून 1967 में सिंगापुर, मलेशिया और ब्रूनई के करेंसी संघ का समापन, तीनों ने अपनी-अपनी करेंसी प्रारंभ की। तीनों की संधि ने इन करेंसियों का समान दर पर विनिमयशील रखा था।	1965 में सिंगापुर की मलेशिया से स्वतंत्रता के बाद करेंसी संघ 1967 में भंग हो गया।	अभी तक ब्रूनई के डालर से परिवर्तनीयता बनी हुई है।
आस्ट्रेलिया	1988 व 2015	सत्तर और अस्सी के दशकों में बहुत शोध अनुसंधान के बाद (उन्त पुनःमुद्रण प्रौद्योगिकी पर आधारित) नकलरोधी पोलिमर नोट 1988 में जारी किए गए। फरवरी 2015 की घोषणा के अनुसार नई पीढ़ी के नोटों में एक ऐसी निर्माणात्मकता होगी कि दृष्टिबाधित व्यक्ति भी उन्हें सहज ही पहचान सकेंगे।	नोटों की नक्काली को रोकना	यह विश्व का पहला देश बन गया, जहां सभी प्रचलित नोट पोलिमर प्रौद्योगिकी पर आधारित है।
यूरो	1999	इस वर्ष तक एक करेंसी अपनाने पर यूरोपीय संघ में 1992 में ही सहमति बन चुकी थी। बहुत सतर्कता पूर्ण नियोजन और इसके प्रारूप स्वरूप की घोषणा के बाद जनवरी 1999 में गैर भौतिक आकार में यूरो प्रारंभ किया गया। जनवरी 2002 तक विभिन्न सदस्यों की पुरानी करेंसियां भी प्रचलन में रही, किंतु उसके बाद से केवल यूरो के नोटों का निर्गम प्रारंभ हो गया। जून 2002 के अंत तक (कुछ बाद तक भी) पुरानी करेंसियां परिवर्तनीय बनी रहीं।	यूरोपीय संघ में एक सांझी करेंसी को प्रचलित करना	यह संक्रांति सामान्यतः विघ्न बाधारहित रही।
सिंगापुर	1999	सितंबर 1999 में परिष्कृत सुरक्षा विशेषताओं सहित चित्रवाले नोट, करेंसी की चौथी श्रृंखला, जारी की गई।	2014 का कदम उच्च मुद्रा के माध्यम से कालाधन सफेद करने पर रोक के लिए था। यह जोखिम बढ़े लेनदेनों में अधिक होता है।	
	2014	S \$ 10,000 के नोट जारी करना बंद कर बैंकों को अक्टूबर 2014 से ग्राहकों को ये नोट वापस परिचलन हेतु देने से मना, किंतु ये अभी तक वैध मुद्रा है।		
कनाडा	2011	जून 2011 में पोलिमर बैंक नोट जारी, जानकारी का व्यापक प्रसार नवंबर में \$100 तथा मार्च 2012 में \$50 के नोट जारी	जनता का करेंसी में विश्वास दृढ़ हुआ, नकली नोट छापना कम हुआ	
डेनमार्क	2012	2009 से 2011 की अवधि में नई बैंक नोट श्रृंखला जारी हुई थी, जिसमें कई नई विशेषताएं थीं। वर्ष 2012 में फेरोइज बैंक नोट श्रृंखला को उच्च स्तर पर पहुँचाया गया।	नकली नोटों की आशंका का सामना	

स्वीडन	2013-2016	बिना चमकीली पट्टी वाले 50 और 100 क्रोना के नोट दिसंबर 2013 के बाद बंद कर दिए गए। अक्टूबर 2015 में 20, 50, 200 और 1000 क्रोना के नए नोट जारी। पुराने नोटों का चलन जून 2016 तक सीमित किया गया, अक्टूबर 2016 में 100 और 500 क्रोना के नए नोट आए, कुछ सिक्के भी जारी किए गए; पुराने नोटों से भुगतान जून 2017 तक स्वीकाय	ये सभी निर्णय बैंक नोटों और सिक्कों की नई श्रृंखला जारी कर पुराने बंद करने के फैसले का अंग है। नए नोट आदि की निकासी 2015 से प्रारंभ की जानी थी।
जिम्बाब्वे	2015	जिम्बाब्वे डालर ZD का विमुद्रीकरण, योजना पूरी तरह से अमेरिकी डालर का प्रयोग करने की थी। यह काम सितंबर 2015 तक पूरा करना था। और अनेक करेंसियों स्वीकार्य बनाई जानी थी	अतितीव्र स्फीति के कारण 2009 से ही ZD का त्याग हो चुका था और देश में अन्य देशों की करेंसियों का प्रयोग मान्य था
पाकिस्तान	2015	जून 2015 में घोषणा कर दी गई कि दिसंबर 2016 से 10, 50, 100 और 1000 रूपए के पुराने स्वरूप के नोट अमान्य हो जाएंगे। नवंबर 2016 तक उन्हें नए नोटों से बदला जा सकता था; हां स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और बैंकिंग सर्विसिज कार्पोरेशन 2021 तक पुराने नोट स्वीकार करते रहेंगे।	भ्रष्टाचार, कालेधन और आतंकवाद पर अंकुश लगाना। परिवर्तन की पुष्टि में कोई स्वीकार्य जानकारी सफलभ नहीं है।
यूरो क्षेत्र	2016	जुलाई 2016 में €50 की नई श्रृंखला जारी, यह अप्रैल 2017 से प्रयोग होने लगेंगे। यूरोपीय केंद्रीय बैंक की घोषणा है कि 2018 के अंत तक €500 के नोट जारी होना बंद हो जाएगा, उस समय €100 और €200 के नोटों की यूरोपा श्रृंखला प्रारंभ हो जाएगी।	यूरो को अधिक सुरक्षित तथा नवीनतम सुरक्षा विशेषताओं से सन्नद्ध बनाना। €500 संबंधी निर्णय का आधार यही था कि इनके कारण गैर कानूनी कामों को बढ़ावा मिलता है।